A Daily News Magazine
भोपाल
सोमवार, 9 जून, 2025
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 22, अंक 270, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2
सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

पहली बात

'जॉकी' राहुल क्या कांग्रेस का 'हार्स-पावर' बढ़ा सकेंगे ?

उमेश त्रिवेदी
प्रधान संपादक

महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक अथवा छत्रपति शिवाजी के सात घोड़े मोती, गजरा, इंद्रायणी, विश्वास, रणवीर, तुरंगी और कृष्णा जैसे अश्व-श्रृंखला की वीर-गाथाओं में इन दिनों एक तथाकथित 'लंगड़ा घोड़ा' सियासी हलकों में काफी चर्चित है। अश्वों की परम्पराओं में हार्स-पावर की वैज्ञानिकता और ऐतिहासिकता को लजाने और ललकारने वाला यह 'लंगड़ा घोड़ा' अनाम है। युद्ध या योद्धाओं की किसी कहानी में 'लंगडे घोड़े' का जिक्र नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी द्वारा मुहावरे के रूप में इसके इस्तेमाल के बाद सियासत के रेसकोर्स में 'लंगड़ा घोड़ा' बाकायदा खड़ा है। रेसकोर्स के ट्रैक पर नाकारा 'लंगड़ा घोड़ा' सियासी रेसकोर्स पर सरपट दौड़ रहा है। राहुल गांधी 'लंगड़े घोड़े' जैसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए आरोपों के कठघरे में हैं।

राहुल ने 3 जून 2025, को भोपाल में 'संगठन सृजन अभियान' के दौरान अक्षम कार्यकर्ताओं के लिए 'लंगड़े घोड़े' शब्द का उपयोग किया था। उनकी राय में अक्षम कार्यकर्ताओं की जगह गतिशील कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा। उनके सभासद इस कथन पर गंभीर थे, लेकिन जयपुर के दिव्यांग अधिकार महासंघ ने भारत सरकार के मुख्य विकलांग आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को इसके विरोध में पत्र लिखा है। उसके अनुसार 'लंगडा' शब्द दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की भावनाओं का उल्लंघन है। मुख्य चुनाव आयुक्त के दिशा-निर्देशों में भी गूंगा, मंदबुद्धि, अँधा, बहरा, लंगड़ा-लूला जैसे शब्दों को अपमानजनक माना गया है। नेता प्रतिपक्ष को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। राहुल के बयान को केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन माना है। यह न सिर्फ अशोभनीय और असंवेदनशील है, बल्कि दिव्यांगजनों का अपमान भी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का यह कटाक्ष गौरतलब है कि गधों की महफिल में घोड़ों की चर्चा कैसे आ गई ? अन्य नेताओं ने भी इसे लेकर राहुल गांधी पर गहरे कटाक्ष किए हैं।

राहुल ने घोड़ों से जुड़े मुहावरों का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया है। अप्रैल 2025 में अहमदाबाद में अभा कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में भी कार्यकर्ताओं के लिए वो 'रेसिंग' घोड़े और 'बाराती' घोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। 'रेसिंग' घोड़े से उनका आशय जुझारू कार्यकर्ताओं से है, जबकि 'बाराती' घोड़ों के रूप में वो कमल-छाप कांग्रेसियों को इंगित करते हैं,जो भाजपा के हाथों में खेलते रहते हैं। भोपाल में राहुल ने कार्यकर्ताओं की दो नस्लों में 'लंगड़ा घोड़ा' भी जोड़ दिया है। इस संज्ञा का प्रयोग निष्क्रिय और निष्प्रभावी कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है।

सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में शुमार स्प्रिटिंग-रेस के अश्व की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसकी धीमी गति चार किलोमीटर प्रति घंटे होती है। सवारों के साथ घोड़े की गतिशीलता पंद्रह-बीस फीसदी कमी आ जाती है। अस्तबल अथवा स्टड-फार्म में प्रशिक्षित घोड़ों की तुलना में जंगली घोड़ों की स्पीड कुछ कम होती है। 'गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में घुड़दौड की सबसे अधिक गति 43.97 मील दर्ज है। 14 मई 1908 को ग्रांटविले, पेन्सिल्वेनिया में पेन नेशनल ग्रांट रेसकोर्स में यह रिकार्ड दर्ज हुआ था।

भाजपा की मजबूत चुनावी-मशीनरी के मुकाबले के लिए कांग्रेस को ताकतवर बनाने की यह संगठनात्मक कवायद दिलचस्प है। किसी पार्टी की राजनीतिक शक्ति उसके कार्यकर्ताओं के समर्पण, प्रतिबद्धता और अनुशासन में अन्तर्निहित होती है। 'पोलिटिकल-साइंस' में संगठनात्मक-शक्ति किसी यूनिट अथवा इकाई के रूप मे परिभाषित नहीं है। साइंस में ऊर्जा या शक्ति का पैमाना हार्स-पावर होता है। राहुल गांधी पार्टी में रेसिंग-घोडे, बाराती घोड़े और लंगड़े घोड़ों की तर्ज पर कार्यकर्ताओं के डीएनए का निरूपण करके कांग्रेस का पोलिटिकल 'हॉर्स-पावर' बढ़ाना चाहते हैं।

राजनीतिक सत्ता में 'हॉर्स-पावर' याने अश्वारोहिणी सेना या घुड़सवारों योद्धाओं का अपना महत्व रहा है। अश्वारोहिणी सेना की बदौलत ही सिकंदर जैसे सम्राटों ने दुनिया जीतने का सपना देखा था। बड़े युद्धों के इतिहास में घुड़सवारों की महती भूमिका रही है। हॉर्स-पावर की तर्ज में सियासी ताकत की बात होती है, तो घोड़ों की वफादारी संवेदनशीलता, और बहादुरी के किस्सों के साथ वो राजसी चेहरे भी इतिहास के पन्नों में उभरने लगते हैं, जो अच्छे घुड़सवार थे। याने वो बढ़िया और बेहतर 'जॉकी' थे। ताजा इतिहास में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को बेमिसाल राजसी जॉकी की श्रेणी में रखा जा सकता है।

पंचतंत्र,हितोपदेश अथवा विदेशी परी-कथाओं में काले-सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार हर व्यक्ति के जहन में काबिज है। सिर्फ महाभारत अथवा रामायण में ही नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में भी 215 बार दिव्य अश्वों की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में घोड़ों के अलावा गाय का उल्लेख 176 बार और बैल की चर्चा 170 की गई है। भारतीय शास्त्रों मे सूर्य भी सात अश्वों को रथ पर सवार हैं। दिव्य अश्वों की तथा-कथा में महात्मा बुद्ध के घोड़े कंटक का नाम भी आता है, जिसे उन्हें उनके पिता ने उपहार में दिया था।

इसी तारतम्य में सिकंदर के घोड़े 'बुसेफालस' का नाम भी आता है। माथे पर सफेद सितारे के अक्स साथ यह काला घोड़ा बेहद आकर्षक था। इस घोड़े के प्रति सिकंदर की चाहत इस कदर थी कि उसने अपने शहरों में से एक शहर का नाम ही 'अलेक्जेंड्रिया बुसेफालस' रख दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट का घोड़ा 'मारेंगो' वाटर-लू समेत आठ लड़ाइयों में अपने सम्राट के साथ आठ बार घायल भी हुआ था। रोमन साम्राज्य के सम्राट जूलियस सीजर के विनम्र, तेजतर्रार और फुर्तीले बहादुर घोड़े का नाम 'ऑस्टुरकोन' था। ग्रीक के मिथकों में ओलंपस राजा जीउस के पास पंख वाले घोड़े का उल्लेख भी है।

दिल्ली के सियासी रेसकोर्स का स्वभाव भी मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स जैसा ही है। ज्यादातर रेसिंग घोड़ों में क्षमता होती है, लेकिन गतिशीलता के लिए उन्हें प्रशिक्षित और प्रेरित करना पड़ता है। जब घोड़े को 'जॉकी' के साथ दौड़ने और लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो घुड़सवार जॉकी को भी घोड़े को आरामदायक बनाने के लिए अपनी शारीरिक-स्थिति को बनाना और स्थिर रखना जरूरी होता है। समय के साथ जानवरों की मांसपेशियों के टोन में भी उल्लेखनीय बदलाव होना चाहिए। ताकि वो लंबी तेज दौड़ पूरी करने में सक्षम बने रहें। घोड़ों में इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए 'जॉकी' ही सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी के संदर्भों में महालक्ष्मी रेसकोर्स और दिल्ली के सियासी-रेसकोर्स में काफी समानता नजर आती है।

'लंगड़े घोड़े' की चर्चाओं के बीच सियासी हलकों में सवाल उठने लगा है कि क्या सियासी रेसकोर्स में राहुल गांधी अच्छे 'जॉकी' सिद्ध हो पा रहे हैं? यदि वो अच्छे 'जॉकी' है तो कांग्रेस के 'रेसकोर्स' में सूनापन, बेचैनी और अधीरता क्यों है? जीत की आश्वस्ति क्यों नहीं है? पुराने नेता और कार्यकर्तापार्टी में असहज क्यों महसूस कर रहे हैं ? पिछले लोकसभा चुनाव में लिस्ट में भाजपा का हर चौथा उम्मीदवार दलबदलू था और हर चौथे उम्मीदवार में एक कांग्रेस से आयातित नेता था। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 417 में से 116 उम्मीदवार दूसरे दलों से आयातित नेता थे और इनमें 37 जाने माने कांग्रेसी नेता थे।

बगावत के इस आकार के मायने क्या ये हैं कि सियासी रेसकोर्स के 'जॉकी' के रूप में राहुल गांधी यह विश्वास पैदा करने में असफल रहे हैं कि वो कांग्रेस के विजय-रथ के समर्थ सारथी हैं? फिलवक्त शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी या आनंद शर्मा जैसे नेता भाजपा के रेसकोर्स में 'कम्फरटेबल' क्यों महसूस कर रहे है? जब शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे पुराने कद्दावर नेताओं के क्रियाकलाप में बगावतका एहसास यह धारणा को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस के सियासी-रेसकोर्स का 'ट्रैक' समतल और समानान्तर नहीं है। और, जॉकी उसकी परवाह नहीं कर पा रहा है।

सुप्रभात

सब कुछ पार्थिव है यहाँ
लेकिन मुलाक़ातें नहीं हैं
पार्थिव
इनकी ताज़गी
रहेगी यहाँ
हवा में !
इनसे बनती हैं नई जगहें
एक बार और मिलने के बाद भी
एक बार और मिलने की इच्छा
पृथ्वी पर कभी ख़त्म नहीं होगी!
– आलोक धन्वा

भारत की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान के 11 वर्ष

डॉ. मोहन यादव
(लेखक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

नये भारत निर्माण के दृष्टा, वैश्विक राजनेता और हमारे मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 11 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिये समर्पित रहा है। यह समय अनूठा, अद्भुत और अकल्पनीय है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को विश्व में मान, सम्मान और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। इस विशेष उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई।

प्रधानमंत्री जी की यह यात्रा देश की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान की यात्रा है। इसमें एक ओर भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, देश का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है और भारत अब डिफेंस इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। वहीं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ मध्यप्रदेश और प्रदेशवासियों को मिल रहा है। इस विशेष संयोग में प्रदेश ने नवाचारों के साथ विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) के सम्मान का मंत्र दिया। उन्होंने इन्हीं चार स्तंभों के समग्र विकास से वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का मार्ग बताया। हमने इन्हीं स्तंभों पर केन्द्रित मिशन बनाकर कार्य आरंभ कर दिया है।

प्रधानमंत्री जी की नीतियों और निर्णयों ने नये आत्मनिर्भर भारत निर्माण को गति दी है। 11 वर्ष पूर्व श्री मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों को नमन करके जो संकल्प व्यक्त किये थे, उनमें उनकी भावी यात्रा के साथ नये भारत निर्माण के संकेत भी थे। उन्होंने निरंतर अपने संकल्पों की सिद्धि के साथ देश को आगे बढ़ाया है और राष्ट्र तथा समाज के उत्थान के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं।

अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, भारत में नागरिकता कानून (सीएए) बनाने, तीन तलाक जैसे अमानवीय कानून को समाप्त करने, वक्फ संपत्ति का मुस्लिम समाज के कल्याण में उपयोग के लिए वक्फ संशोधन विधेयक कानून लाने जैसे निर्णय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से ही संभव हुए हैं। उनका दृढ़ संकल्प सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भी दिखाई दिया। बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत के सामर्थ्य को पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में बहनों के सामने आतंकियों ने उनका सिंदूर मिटाया था, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित कर दिया कि यह नया भारत है जो राष्ट्र के सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा और मानवता के लिए घर में घुसकर भी मारना जानता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल की यह समृद्ध यात्रा राष्ट्र की उन्नति, आधारभूत समस्याओं के निराकरण और वैश्विक छवि के उत्थान की रही है। देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क अन्न, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्का घर, हर घर में शौचालय, 15.6 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल, 10 करोड़ से अधिक घरों में उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन और गांवों को रोशन किया है। उनके स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छता एवं साफ सफाई में जुट गया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के इंदौर को लगातार सात बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार और मध्यप्रदेश को दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का उद्घोष किया। उनकी नीतियों में अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की अवधारणा है। सबके स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए 'आयुष्मान भारत' अभियान चलाया। इसमें 9 करोड़ से अधिक लोगों का मुफ्त उपचार हुआ है। सत्तर वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी निःशुल्क उपचार मिला है। 16 हजार से अधिक जन औषधि केन्द्रों से सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध करवाई है। कोरोना काल में देशवासियों को आपदा में अवसर का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण का संकल्प दिया और देशवासियों को स्वदेशी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई। इस भारतीय वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने भी स्वीकारा। उन्होंने श्रृंखलाबद्ध लोक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के समग्र विकास की समुचित व्यवस्था की। जनधन योजना से 55 करोड़ से अधिक लोगों को वित्तीय धारा से जोड़ा गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से गरीबों को 44 लाख करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। पीएम स्वनिधि और स्ट्रीट वेंडर से रेहड़ी-पटरी के व्यवसायियों को आधार दिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी, युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए, नई शिक्षा नीति के साथ 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास और 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप्स शुरू कर युवाओं को विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिये भागीदार बनाया है। मध्यप्रदेश ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को अमल में लाया और युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोज़गार तथा स्व-रोज़गार के लिये अनंत संभावनाए विकसित की हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 7.7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा से अन्नदाताओं को संबल मिला है। महिलाओं की सुरक्षा के उपाय, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। देशभर में लगभग 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हुई हैं इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में लगभग 5 लाख स्व सहायता समूहों से 62 लाख महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं।

वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीतियों, विशेषकर नोटबंदी जिससे कदाचार पर नियंत्रण हुआ, डिजिटलाइजेशन और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से ऑनलाइन लेनदेन का चलन बढ़ा। इन सभी नीतियों ने आर्थिक विकास के निर्णयों को सबल किया और भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया।

प्रधानमंत्री जी ने विकास के साथ विरासत का आह्वान किया है। विरासत को सहेजने के लिए उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास और पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य आरम्भ किया तथा इसे धार्मिक पर्यटन से जोड़ा। लोगों का अपनी विरासत के प्रति सम्मान बढ़ने के साथ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। नमामि गंगे योजना से पवित्र नदियों की सफाई अभियान के साथ जल संरक्षण की परम्परा विकसित हो रही है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्यप्रदेश में विकास के साथ विरासत के संकल्प को आत्मसात किया और भव्य और दिव्य महाकाल महालोक का निर्माण किया। श्रीराम वन गमन पथ, श्रीकृष्ण पाथेय निर्माण और विक्रमोत्सव का आयोजन किया है। प्रदेश को केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल रिवर लिंक परियोजनाओं की सौगात मिली है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए श्री मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल और ग्लोबल का आह्वान किया। मध्यप्रदेश में हमने प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों के अनुरूप उद्योग स्थापित करने का नवाचार प्रारंभ किया है। इसके लिए पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फिर महानगरों और विदेशों में रोड शो तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के बाद अब सेक्टर आधारित समिट के विस्तार का उपक्रम शुरू किया है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा।

श्री मोदी जी ऐसे युगदृष्टा हैं जिन्होंने आधारभूत समस्याओं के समाधान और विरासत को सहेजने के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की भी नई उड़ान भरी है। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का आह्वान किया था जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) के वैज्ञानिकों से स्वयं चर्चा की और आवश्यक बजट तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इसका परिणाम यह है कि भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान तकनीक विश्व में अग्रणी बनी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया।

कनेक्टिविटी से विकास को गति प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री जी ने सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार, 23 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति, बंदरगाह, हवाई मार्ग, हाई स्पीड कॉरिडोर निर्माण के लक्ष्य को स्वरूप प्रदान किया है। अटल टनल और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब आकार ले चुका है।

प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी वर्ष 2047 तक भारत को 35 ट्रिलियन डॉलर की पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था बनाना और विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस संकल्प की पूर्ति में मध्यप्रदेश सहभागी बनने के लिये प्रतिबद्ध है। उनके आशीर्वाद और सहयोग से मध्यप्रदेश प्रगति के साथ नया इतिहास रच रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नये भारत निर्माण लक्ष्य को सार्थक करने में मध्यप्रदेश की अग्रणी भूमिका रहेगी।

समंदर में लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा है भारत

● अब इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली नई जेट्टी की सुविधा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर एक नई समर्पित जेट्टी का उद्घाटन किया। 76.7 मीटर लंबा यह अत्याधुनिक बर्थ भारतीय तटरक्षक बल जहाजों की त्वरित तैनाती और वापसी सुनिश्चित करेगा। इस जेट्टी से तटीय निगरानी, खोज और बचाव, तस्करी विरोधी अभियान और मछली पालन सुरक्षा जैसी अभियानों

की तत्परता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह जेट्टी रणनीतिक रूप से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनों से मात्र 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। यह विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीपवाटर पोर्ट के समीप है, जिससे यह भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर भारतीय तटरक्षक क्षेत्र (पश्चिम) के कमांडर, महानिरीक्षक भीष्म शर्मा, विझिनजाम इंटरनेशनल सी-पोर्ट लिमिटेड, केरल सरकार, केरल समुद्री बोर्ड, राज्य पुलिस, पोर्ट प्राधिकरण, भारतीय सेना, अदाणी पोर्ट्स प्रा. लि. और मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आयोजित कोल जनजातीय सम्मेलन में होंगे शामिल

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहडोल जिले के ब्यौहारी में भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कोल जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव 80 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 55 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 250 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 52 विकास कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित करेंगे। यह सम्मेलन राज्य सरकार की जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास और उत्थान के लिये प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोक निर्माण विभाग के 6 कार्य (रू. 31.45 करोड़), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 33 कार्य (रू. 22.64 करोड़), मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का 1 कार्य (रू. 10 करोड़), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 10 कार्य (रू. 6 करोड़), लोक निर्माण विभाग (सेतु) का 1 कार्य (रू. 4.75 करोड़), जनजातीय कार्य विभाग का 1 कार्य (रू. 2.75 करोड़), लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 3 (रू. 1.47 करोड़) कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के 15 कार्य (रू. 121.92 करोड़), मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के 5 कार्य (रू. 94.49 करोड़), ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 8 कार्य (रू. 9.17 करोड़), लोक निर्माण विभाग के 6 अन्य कार्य (रू. 7.69 करोड़), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 16 कार्य (रू. 7.06 करोड़), लोक निर्माण विभाग (सेतु) का 1 कार्य (रू. 3.29 करोड़) और मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन का 1 कार्य (रू. 0.47 करोड़) का भूमि-पूजन करेंगे।

मुख्यमंत्री आज गाडरवारा में करेंगे 80 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 जून को नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में एक भव्य आयोजन में 80 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत के 135 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 56 करोड़ 58 लाख रुपये के 67 कार्यों का लोकार्पण और 23 करोड़ 88 लाख रुपये के 68 कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जल जीवन मिशन के अंतर्गत 396 लाख रुपये की लागत से देवरी से बनवारी पिपरिया तक 8.27 किमी सड़क, साईखेड़ा में सीवरेज मलजल योजना तथा पुस्तकालय एवं प्रतीक्षालय जैसे शहरी विकास से जुड़े कार्यों का लोकार्पण और 23 करोड़ 88 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। जिले में सामुदायिक भवन, अमृत सरोवर 2.0, आंगनबाड़ी भवनों और अन्य बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 38 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 9 जून 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

लॉरेंस गैंग से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने किया किनारा

- सलमान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी-मूसेवाला की हत्या जैसी वारदातें साथ कर चुके

जालंधर (एजेंसी)। देश और विदेश में अपना नेटवर्क चलाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस का गैंग दो फाड़ हो गया है। कनाडा से लॉरेंस का गैंग संभाल रहा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अब रोहित गोदारा को साथ लेकर अलग हो गया है। इन गैंगस्टरों ने साथ मिलकर सलमान खान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी का मर्डर जैसी चर्चित वारदातों को अंजाम दिया था। लॉरेंस गैंग और पंजाब पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस और उसका भाई अनमोल बिश्नोई हैं।

संरक्षक लुटेरा बन जाए, तो उसे सजा देना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट बोला, आईटीबीपी जवान की बर्खास्तगी को रखा बरकरार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब संरक्षक ही लुटेरा बन जाए जो उसे सजा देना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसने कैश लूट मामले में एक कॉन्स्टेबल को बर्खास्त कर दिया था। मामला साल 2005 का है, कॉन्स्टेबल को जवानों की सैलरी के लिए लाए गए कैश बॉक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में कॉन्स्टेबल ने बॉक्स का ताला तोड़कर कैश निकाल लिया था। आईटीबीपी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बाद में जवान उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने आईटीबीपी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कहा कि, इस तरह के अपराधों में दोषी पाए गए कॉन्स्टेबल को उचित दंड देना अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा- जब बात सुरक्षाबलों की हो, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, जहां जिम्मेदारी की बात हो तो अर्धसैनिक बलों में इसकी भावना और अधिक होनी चाहिए। जहां अनुशासन, नैतिकता, निष्ठा, सेवा के प्रति समर्पण और विश्वसनीयता नौकरी के लिए आवश्यक हैं। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टेबल जागेश्वर सिंह एक अनुशासित अर्धसैनिक बल का सदस्य था, जो एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र में तैनात था। उसे कैश बॉक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, उसने अपने विश्वास और भरोसे को दरकिनार कर कैश बॉक्स को तोड़ दिया। कॉन्स्टेबल जागेश्वर सिंह को 30 नवंबर, 1990 को आईटीबीपी में भर्ती किया गया था और वह 4-5 जुलाई, 2005 की मध्यरात्रि को कोटे में संतरी के रूप में ड्यूटी कर रहा था, जहां जवानों को सैलरी के रूप में दिए जाने वाले लाखों रुपए से भरे कैश बॉक्स रखे हुए थे। सिंह ने कथित तौर पर ताला तोड़ दिया और नकदी ले ली, इसके बाद कैश बॉक्स को कोटे से लगभग 200 गज की दूरी पर छिपा दिया और पोस्ट से भाग गया। जब घटना कंपनी कमांडर को पता चली तो उन्होंने तुरंत आस-पास के इलाके के साथ-साथ उत्तरकाशी की ओर जाने वाले वाहन की भी तलाशी ली, लेकिन आरोपी भाग निकला। कंपनी कमांडर ने तब मामले की सूचना बटालियन के कमांडिंग ऑफीसर को दी और बाद में 6 जुलाई, 2005 को कॉन्स्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी हुई, जिसमें जवान दोषी पाया गया।

चिराग पासवान के ऐक्टिव होने से बिहार बीजेपी सतर्क

- 'किंग मेकर' गेम प्लान के खुलासे के बाद एनडीए में हलचल

पटना (एजेंसी)। हाल के हफ्तों में, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से बिहार लौटने और विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई, जिसे राज्य की राजनीति में किंगमेकर या किंग नहीं तो किंग की भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है। और यह संदेश भाजपा नेतृत्व के लिए भी सही है। जबकि भाजपा नेतृत्व

का कहना है कि पासवान अपनी पार्टी को सीट बंटवारे के तहत आवंटित किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं , सत्तारूढ़ पार्टी के एक वर्ग का कहना है कि वह केवल राज्य इकाई में भ्रम की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पासवान ने हाल ही में कहा कि वह बिहार की राजनीति में वापस आने के लिए तैयार हैं क्योंकि राज्य के विकास में योगदान देना हमेशा से उनकी प्रेरणा रही है।

दक्षिण में होगी भारी बारिश उत्तर अभी भी रहेगा सूखा!

हो जाएं अलर्ट! मौसम विभाग की ने दे दी चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर भारत में भले ही भीषण गर्मी पड़ रही हो, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। परसों यानी कि 10 जून से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बहुत भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं, उत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में 8-11 जून और हिमाचल व उत्तराखंड छोड़कर उत्तर पश्चिम के अन्य राज्यों में अगले चार दिनों तक हीटवेव चलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 11-14 जून, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 10-13 जून को बहुत भारी बरसात होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में 10-14 जून, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में 11-14 जून, लक्षद्वीप में 13 व 14 जून को बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, इंटीरियर कर्नाटक के इलाकों में 12 जून को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी व मध्य भारत की बात करें तो अंडमान व निकोबार, ओडिशा में 8-12, मध्य प्रदेश में 8 व 9, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल में 11 और 12 जून, बिहार, झारखंड में 11-14 जून के बीच हल्की से मध्यम बरसात होगी। बिहार व विदर्भ में 11, 12 जून को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11-14 जून, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 व 14 और पंजाब में 14 जून को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, इस दौरान गर्मी भी बनी रहेगी। इसके अलावा, उत्तराखंड में 12-14 जून के बीच तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा।

ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे

राहुल को फडणवीस का जवाब, 'मैच फिक्सिंग' के आरोप पर घेरा

मुंबई (एजेंसी)। राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 'मैच फिक्सिंग' के आरोप पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब आया है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहाकि ताउम्र आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहाकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों में हार पर आत्मावलोकन करने के बजाय जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। फडणवीस ने समाचार पत्र में प्रकाशित अपने लेखों में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बिहार सहित आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें मिलने वाली हार के लिए बहाने तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को कई अखबारों में प्रकाशित एक लेख और एक्स पर पोस्ट साझा कर आरोप लगाया था। इसमें उन्होंने कहाकि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था और यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा कर गांधी ने चुनाव में कथित अनियमितताओं के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया कि कैसे मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया। मतदान प्रतिशत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया। फर्जी मतदान

कराया गया और बाद में सबूतों को छिपा दिया गया। निर्वाचन आयोग ने आरोप को खारिज करते हुए कहाकि अनुकूल परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। गांधी के दावों के जवाब में फडणवीस ने सब कुछ बताया है।

मैतेई लीडर की गिरफ्तारी से फिर सुलगा मणिपुर

- प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डाला
- कई गाड़ियां फूंकीं, पत्थर से भी हमला, 5 जिलों में इंटरनेट बंद

इंफाल (एजेंसी)। 3 मई 2023 को कुकी-मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। इन दो सालों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा घायल हुए। 70 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। 6 हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। मणिपुर में मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता करन सिंह को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 2023 में हिंसा भड़काने के आरोप है। इनकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद शनिवार देर रात मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी। राजधानी इंफाल के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी, सड़कों पर टायर और पुराने फर्नीचर भी जलाए। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की। सरकार ने 7 जून की रात 11:45 बजे से पांच दिनों के लिए 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी है। इनमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर शामिल हैं। इंफाल ईस्ट और बिष्णुपुर में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मणिपुर में 3 मई 2023 को कुकी-मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा घायल हुए। 70 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। 6 हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की।

असम से बाहर निकाले जाएंगे अवैध बांग्लादेशी

- सरमा बोले-अब 1950 में बने कानून का होगा इस्तेमाल

दिसपुर (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब अवैध प्रवासियों की पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के निष्कासन के लिए विदेशी न्यायाधिकरणों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, सरकार अब सीधे 1950 के कानून का उपयोग करेगी, जो अभी भी कानूनी रूप से मान्य है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा,सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6 पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि हर मामले में न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। असम में प्रवासियों को सीधे निष्कासित करने के लिए पहले से ही एक वैध कानून मौजूद है।

जस्टिस यशवंत वर्मा उठा सकते हैं बड़ा कदम

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाने के लिए राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू कर दी है। अब जस्टिस वर्मा के सामने महाभियोग से बचने का केवल एक ही विकल्प है। अगर वह प्रस्ताव आने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो महाभियोग से बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हटाने के मामलों के जानकार लोगों का कहना है कि संसद में खुद का बचाव करने से बचने के लिए वह मौखिक रूप से ही इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। अगर वह खुद से ही इस्तीफा दे देते हैं तो रिटायर्ड हाई

कोर्ट के जज की तरह ही उन्हें पेंशन और बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी। हालांकि अगर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाना पड़ता है तो उन्हें पेंशन तक नहीं मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक हाई कोर्ट के जज राष्ट्रपति को

- महाभियोग से बचने का अब बचा है एक ही रास्ता
- मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार भी हुई ऐक्टिव

पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें किसी की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती है। इस्तीफा देने के लिए जज का पत्र ही काफी होता है। अगर जज अपने पत्र में इस्तीफा देने की कोई तारीख बताता है तो उसतारीख से पहले उसके पास इस्तीफा वापस लेने का भी अधिकार होता है।

राफेल जेट को अब मिलेगा 'मेक इन इंडिया' का टच

ग्लोबल एयरोस्पेस हब बनने के लिए है तैयार है भारत!

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के टाटा ग्रुप ने मिलकर हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमानों का फ्यूजलेज बनाने का फैसला किया है। फ्यूजलेज विमान का मुख्य ढांचा होता है। यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुए 63,887 करोड़ रुपये के बड़े समझौते का हिस्सा है। इस समझौते में भारत की नौसेना के लिए 26 राफेल-मरीन जेट विमान खरीदे जाएंगे। इन विमानों की डिलीवरी 2028 से 2030 के बीच होने की उम्मीद है। यह पहली बार है कि डसॉल्ट कंपनी फ्रांस के बाहर राफेल विमान के फ्यूजलेज का उत्पादन करेगी। हैदराबाद में बनने वाली यह यूनिट बहुत महत्वपूर्ण होगी। इससे पता चलता है कि भारत की एयरोस्पेस निर्माण क्षमता पर भरोसा बढ़ रहा है। इस नई यूनिट में मल्टी-रोल फाइटर जेट के कई महत्वपूर्ण हिस्से बनेंगे। इनमें लेटरल रियर शेल, फुल रियर सेक्शन, सेंट्रल फ्यूजलेज और फ्रंट सेक्शन शामिल हैं। भारतीय वायु सेना पहले से ही राफेल विमानों का इस्तेमाल कर रही है। इस कदम से भारत की भूमिका इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में और भी मजबूत होगी। हैदराबाद में यह दूसरा बड़ा एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग साइट होगा। इससे पहले टाटा-बोइंग का जॉइंट वेंचर भी यहां अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के फ्यूजलेज बनाता है। इन हेलीकॉप्टरों को भारत ने अमेरिका से खरीदा है। डसॉल्ट-टाटा की यह साझेदारी ऐसे समय में हो रही है जब भारत सरकार अपने नेक्स्ट-जेनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल रही है। इसमें सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल होगी। विदेशी कंपनियों के साथ बढ़ते सहयोग, घरेलू इनोवेशन और सरकारी मदद से

अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन सकता है। डसॉल्ट और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के बीच सहयोग से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात को कम किया जाए। इसे ही 'आत्मनिर्भरता' कहा जा रहा है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। लेकिन 2020 से 2024 के बीच उसके सैन्य आयात में 9.3 फीसदी की कमी आई है। इसकी तुलना 2015-2019 के पिछले पांच वर्षों से की गई है। फ्यूजलेज किसी भी लड़ाकू विमान का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका स्थानीय स्तर पर निर्माण होना इस बात का संकेत है कि भारत एयरोस्पेस उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद की यह फैसिलिटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4.5-जनरेशन का राफेल विमान भारत के 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट में सबसे आगे है। इस प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती अनुमानित लागत 1.25 लाख करोड़ रुपये है। भारतीय वायु सेना में फाइटर जेट की कमी को पूरा करने के लिए इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। डसॉल्ट और टाटा ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि पहले फ्यूजलेज सेक्शन वित्त वर्ष 2028 में बनने शुरू हो जाएंगे। इस फैसिलिटी से हर महीने दो पूरे फ्यूजलेज बनाने की उम्मीद है। यह फैसिलिटी एक हाई-प्रिसिजन एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में काम करेगी। यह न केवल भारत की रक्षा तैयारियों में योगदान देगा, बल्कि ग्लोबल मदद करेगा।

मिशन कर्मयोगी में नगरीय प्रशासन एवं विकास के 43 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पंजीकृत

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन कर्मयोगी की अवधारणा और कार्य-प्रणाली को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण नीति तैयार की है। इस नीति में प्रत्येक विभाग के बजट में मिशन कर्मयोगी के लिये बजट का एक प्रतिशत आरक्षित किया गया है। इस व्यवस्था से कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिये आवश्यक संसाधन सुनिश्चित हो रहे हैं। यह व्यवस्था संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में भी लागू की गयी है।

मिशन कर्मयोगी डिजिटल पोर्टल पर अब तक 43 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पंजीकृत किया जा चुका है। ये कुल कर्मचारियों का लगभग 70 प्रतिशत है। संचालनालय के 8816 प्रतिभागी पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं, जिनमें से 6843 अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। विभाग द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से 4 ई-लर्निंग मॉड्यूल निर्मित किये गये हैं। इनमें आश्रय-स्थल प्रबंधन, स्व-सहायता समूह गठन एवं प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शामिल हैं।

प्रदेश की क्षमता निर्माण नीति मिशन कर्मयोगी के आदर्शों पर आधारित एक ठोस एवं दायित्वपूर्ण रणनीति है। इससे राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की कौशल और नेतृत्व क्षमता लगातार बढ़ेगी। राज्य सरकार की यह पहल केन्द्र सरकार की नीति से मेल खाती है। प्रशिक्षित प्रशासन तंत्र से सक्षम उत्तरदायी सुशासन व्यवस्था को साकार किया जा रहा है।

महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड किया

बेटे ने सबसे पहले फंदे पर लटका हुआ देखा, पुलिस जांच में जुटी

भोपाल (नप्र)। भोपाल की कोकता मल्टी में रहने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना शनिवार रात की है। रविवार दोपहर पीएम के बाद बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

मृतका की शादी को 15 साल बीत चुके हैं। उसके 8 और 12 वर्ष के दो बेटे हैं। पुलिस के मुताबिक अनिता अहिरवार पति मुकेश अहिरवार (35) मल्टी कोकता में रहती थी। शनिवार रात बच्चे घर के बाहर खेलने गए थे। पति हलवाई हैं और काम पर गए थे। कुछ देर में उनका 12 वर्षीय बेटा घर के अंदर पहुंचा।

उसने देखा की मां फांसी के फंदे पर लटकी हैं। उसने तत्काल पिता को मामले की जानकारी दी। पिता ने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने शव को फंदे से उतारा। पति ने घर पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए रवाना किया। रविवार को बॉडी पीएम के बाद परिजनों को सौंप दी गई। पुलिस को फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतका के मायके पक्ष ने भी कोई आरोप नहीं लगाए हैं। पुलिस मामले की सभी एंगल पर जांच कर ही है।

इंस्टा फ्रेंड ने किया युवती से रेप

प्रेग्नेंट हुई तो खाई गर्भपात की दवा, अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

भोपाल (नप्र)। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक-युवती में प्रेम प्रसंग हो गया। आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर युवती को मिलने बुलाया। हबीबगंज इलाके की एक होटल में लड़की से रेप किया। विरोध करने पर जल्द शादी करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद तीन साल तक दोनों रिलेशन में रहे। पिछले दिनों लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो युवक ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने गर्भपात के लिए दवा खा ली।

युवती की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल से पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना के बाद कोलार पुलिस ने जीरो पर रेप केस दर्ज कर डायरी हबीबगंज पुलिस को सौंप दी है। एसआई मुक्ता शर्मा ने बताया कि 21 वर्षीय पीड़िता कोलार इलाके में रहती है। ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट जॉब कर रही है। वर्ष 2023 में उसकी बात इंस्टाग्राम पर चिराग सिंह से होने लगी।

चैटिंग से शुरू हुआ प्रेम प्रसंग

इंस्टाग्राम पर चैटिंग के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और कॉल पर बात होने लगी। 18 फरवरी 2023 में चिराग ने पीड़िता को मिलने बुलाया और हबीबगंज स्टेशन के करीब एक होटल में ले गया। यहां उसने लड़की से जबरन संबंध बनाए। विरोध करने पर जल्द शादी करने का भरोसा दिलाया।

अलग-अलग स्थानों पर कई बार की ज्यादती

बाद में आरोपी पीड़िता को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर ज्यादती करता रहा। पिछले दिनों लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसने यह बात चिराग को बताई तो उसने बातचीत बंद कर दी। इससे तंग आकर पीड़िता ने स्वयं गर्भपात का फैसला लिया। इसके लिए उसने एक दवा खाई जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां उसका इलाज जारी है। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पीड़िता को केवल आरोपी का नाम और मोबाइल नंबर मालूम है। वह स्वयं को चूना भट्टी का रहने वाला बताता था।

भोपाल में 10 जून से शुरू होगा 'आम महोत्सव'

डिस्प्ले होगा 2000 रुपए किलो का 'नूरजहां', रीवा का शुगर-फ्री 'सुंदरजा' भी रहेगा आकर्षण का केन्द्र

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट स्थित नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में 'राज्य स्तरीय आम महोत्सव 8.0' की शुरुआत 10 जून से होगी। 14 जून तक चलने वाले इस आयोजन में मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों से लाए गए प्राकृतिक रूप से पके रसायनमुक्त आमों की 15 से अधिक किस्में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी।

इस वर्ष महोत्सव की खास बात यह है कि पहली बार दुर्लभ नूरजहां आम बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इससे पहले यह आम केवल प्रदर्शनी के लिए रखा जाता था। इस आम की कीमत 2,000 प्रति किलो है और इसका वजन 1.1 किलो से अधिक का होता है।

नूरजहां आम का उत्पादन केवल आलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में होता है, जहां इसकी खेती केवल 10 पेड़ों पर होती है। यह आम इतना भारी होता है कि हल्की हवा से भी गिर सकता है, इसलिए इसकी खेती एक चुनौती है।

शुगर के मरीजों के लिए उपयुक्त 'सुंदरजा' आम- रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र से लाया गया जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम भी खास आकर्षण रहेगा। यह आम फाइबर-फ्री होता है और शुगर मरीजों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी मिठास और गुणवत्ता इसे विशेष बनाती है।

नाबार्ड की चीफ जनरल मैनेजर सी. सरस्वी ने बताया कि वाड़ी परियोजनाओं से जुड़े आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, उनकी आजीविका को सशक्त करना और विपणन कौशल विकसित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। आम महोत्सव वाड़ी से थाली तक की अवधारणा को साकार करता है।

ये किस्में भी रहेंगी उपलब्ध

मल्लिका- यह आम आमतौर पर भोपाल में कम ही मिलता है। इसकी ग्राफ्टिंग नीलम और दशहरी आम को मिलाकर की जाती है। इसमें दोनों का स्वाद होता है। यह एक तरह का खट्टा-मीठा आम है। आमतौर पर यह शहडोल क्षेत्र में ही मिलता है। क्योंकि वहां का वातावरण इस आम के लिए अच्छा है।

आम्रपाली- यह अपनी ही तरह का आम है। इसकी ग्राफ्टिंग नीलम और मल्लिका को मिलाकर की गई है। आम तौर पर यह आम उत्तरप्रदेश में फेमस है। क्योंकि शहडोल में यूपी से सटे इलाके में इसे लगाया जाता है। इसको खाने में आपको नीलम और मल्लिका का स्वाद एक साथ मिलेगा।

मालदा-मालदा आम की गुठली छोटी होती है। पल्प यानी गूदा दूसरी वैराइटी की तुलना में 20 प्रतिशत तक अधिक होता है। यह पूरी तरह से मीठा होता है। वहीं, दशहरी और केसर में भी टेस्ट थोड़ा अलग मिलेगा। क्योंकि इलाकों के अनुसार इनके टेस्ट में भी थोड़ा अंतर होता है।

45 साल से कम उम्र के होंगे नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष

ऑब्जर्वर्स से प्रदेश प्रभारी बोले- पैनल में उन्हीं को रखें जिनको पार्टी में 5 साल से ज्यादा हुए

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष 35 से 45 साल की उम्र के होंगे। यह बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने रविवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में कही। उन्होंने कहा, 5 साल से पहले पार्टी में शामिल नेताओं को पैनल में न जोड़ें।

मध्यप्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली और भोपाल से नियुक्त ऑब्जर्वर्स की तीन सदस्यीय टीम अब हर जिले में जाकर जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तलाशेगी। इसके साथ ही जिले में कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी के कारणों की वजह भी तलाशेगी। पीसीसी से नियुक्त किए गए 165 ऑब्जर्वर्स की आज रविवार को जूम मीटिंग हुई।

इस वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित प्रदेश भर के ऑब्जर्वर जुड़े थे। 3 जून मंगलवार को राहुल गांधी भोपाल आए थे। उन्होंने मध्यप्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी।

45 साल से कम उम्र का हो जिला अध्यक्ष- वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा, एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर अपने जिले में दौरे का कार्यक्रम बनाकर नीयत समय पर पहुंचें। जिला कांग्रेस कमेटी जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करेगी। जिला अध्यक्ष के लिए 6 नामों का पैनल तैयार करना है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जिला अध्यक्ष के लिए 35 साल से 45 साल के बीच की उम्र के नेता ही पैनल में शामिल हों।

यदि कोई सशक्त व्यक्ति और विचारधारा से जुड़ा हुआ सीनियर दावेदारी करता है तो उसे विशेष परिस्थितियों में शामिल किया जा सकता है। कोई मजबूत कार्यकर्ता आयुसीमा के चक्कर में छूट न जाए। लेकिन, राहुल जी की सोच है कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष युवा हो, तकनीक फ्रेंडली हो, सोशल मीडिया पर सक्रिय हो। ये सारी खूबियों वाले कार्यकर्ताओं को आप पैनल में शामिल करें।

पैनल में ये 6 प्रकार के नाम होंगे शामिल- हर जिले से जिला अध्यक्ष के लिए पैनल में 6 नाम शामिल किए जाएंगे। इनमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला के नाम हर हाल में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद दो अन्य दावेदारों के नाम पैनल में शामिल रहेंगे।

किसी नेता के होटल में न रुकें, सुविधाओं का लाभ न लें- प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा चाहे एआईसीसी के ऑब्जर्वर हों या पीसीसी के पर्यवेक्षक हों। कोई भी किसी जिले में किसी नेता के होटल और घर पर न रुकें। न ही किसी स्थानीय नेता के साथ दौरे करें। आपके पूरे प्रवास की व्यवस्था एआईसीसी के निर्देश पर कराई जा रही है।

पर्यवेक्षक बोले- जिले में टीम जाएगी, हम बाहर होंगे तो सुझाव कैसे देंगे

एक ऑब्जर्वर ने कहा- पूरे प्रदेश में 10 जून से 30 जून के बीच ऑब्जर्वर जाएंगे। हम दूसरे जिले के पर्यवेक्षक हैं। ऐसे में यदि हम अपने आवंटित जिले में जिस दिन दौरे पर हैं और उसी दिन हमारे गृह जिले में ऑब्जर्वर बैठक करने आएंगे तो हम अपने जिले में ही सुझाव नहीं दे पाएंगे। इस पर प्रदेश प्रभारी ने कहा- आप लोग अपने सुझाव लिखित में अपने गृह जिले के ऑब्जर्वर्स को दे दें। उन्हें मान्य किया जाएगा।

जिले का डेटा हर टीम के पास

राहुल गांधी के साथ 3 जून को हुई बैठक के बाद सभी ऑब्जर्वर्स को आवंटित जिले का जातिगत डेटा फोल्डर में दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस जिले में किस जाति की संख्या ज्यादा हैं और कौन से समाज के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिलाध्यक्ष के पैनल में इस डेटा के आधार पर भी लोग पैनल में शामिल किए जाएंगे।

पर्यवेक्षकों ने पूछा- नए नेता दावेदार तो क्या करें

मीटिंग में एक पर्यवेक्षक ने पूछा कि यदि कोई नेता दो साल पहले पार्टी में शामिल हुआ। वो पार्टी में काम भी कर रहा है और यदि वह जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे है तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर हरीश चौधरी ने कहा, जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से पार्टी में काम करने वाला होना चाहिए।

भितरघात की शिकायत तो नहीं कर पाएंगे दावेदारी

बैठक में एक पर्यवेक्षक ने पूछा कि जिनके खिलाफ भितरघात और चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें हैं, वे यदि दावेदारी कर रहे हैं तो क्या करना होगा? इस पर हरीश चौधरी ने कहा- यदि 5 साल के भीतर चुनावों में भितरघात की शिकायतें है और वे शिकायत सही हैं तो ऐसे लोगों को पैनल में नहीं जोड़ना चाहिए।

दूसरे एरिये में माल बेचा तो कंपनी की करेंगे शिकायत

भोपाल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की मीटिंग में निर्णय; कई मुद्दों पर मंथन

भोपाल (नप्र)। ई-कॉमर्स या मॉडर्न ट्रेड वाली कंपनियों ने मार्केट में अपना माल दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में बेचा तो इसकी शिकायत जीएसटी काउंसिल में की जाएगी। यह निर्णय भोपाल के एमपी नगर में हुई भोपाल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा में लिया गया।

एमपी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील जैन (501) की मौजूदगी में यह बैठक हुई। इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी के सभी सदस्य और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद थे। अध्यक्ष जैन ने व्यापारिक, नगर निगम, यातायात पुलिस, प्रशासन और कंपनियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। इसके अलावा संस्था के नए नियम जैसे- चेक बाउंस होने पर पैनाल्टी का प्रावधान, दो बार से अधिक चेक बाउंस होने पर उस व्यापारी से अगली बार चेक ना लिए जाने के संबंध में, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के स्टाफ द्वारा चोरी या गबन करने के पश्चात उस कर्मचारियों को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां नौकरी पर न रखने के संबंध में चर्चा भी शामिल हैं।

नए नियमों से अवगत भी कराया- बैठक में नए नियमों से सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके अलावा सदस्यता को बढ़ाना, ई-कॉमर्स, इनफील्ट्रेशन आदि समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश मेहता, सचिव सुनील जैन हरिओम, कोषाध्यक्ष अभिजीत सिंह ओबेरॉय, सह सचिव मनीष अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य दीपक मुल्तानी, ललित अग्रवाल, चंद्र भाई, अमित बढ़कूल, दिलीप, संजय राठी ने अपने विचार रखें। सभा में भोपाल डीलर्स एसोसिएशन के दो संरक्षक सदस्य राजेंद्र राजदेव एवं अर्जुन दास संगतानी का सम्मान भी हुआ। वहीं, सभी सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

50 हजार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रेजरी से नहीं निकाली

कांग्रेस ने कहा- 230 करोड़ का घोटाला, ये भूतिया कर्मचारी, टीएमसी बोली- सीबीआई-ईडी सो रही

भोपाल (नप्र)। मप्र के करीब 50 हजार सरकारी कर्मचारी वित्त विभाग के लिए रहस्य बन गए हैं। इन कर्मचारियों की सैलरी पिछले 6 महीने से सरकारी खजाने से नहीं निकाली गई है। सरकारी रिकॉर्ड में इनके कोड एक्टिव हैं। 230 करोड़ रुपए खजाने में अटके पड़े हैं। इनकी सैलरी कभी भी आहरित की जा सकती है।

इधर, मामला सामने आने के बाद देशभर के विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। टीएमसी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए पूछा कि वेतन घोटाले पर ईडी, आयकर और सीबीआई सो रही हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये सभी घोस्ट एम्पलाई हैं। न इनकी पहचान है, न उपस्थिति।

ट्रेजरी कमिश्नर ने प्रदेशभर से मांगा रिकॉर्ड- दरअसल, 23 मई को मप्र के ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने प्रदेश के सभी जिला कोषालय अधिकारी को एक लेटर लिखा था। इसमें सभी अफसरों से सर्टिफिकेट मांगा गया है कि उनके ऑफिस में कोई 'अनधिकृत' कर्मचारी काम नहीं कर रहा।

दिसंबर 2024 से नहीं निकाला वेतन- लेटर में कहा गया है कि आईएफएमआईएस सिस्टम में ऐसे रेगुलर और नॉन-रेगुलर कर्मचारियों का डेटा संलग्न है जिनकी सैलरी दिसंबर 2024 से नहीं निकली। इनके कोड सक्रिय हैं लेकिन मृत्यु या सेवानिवृत्ति तिथि की आईएफएसआईएस में प्रविष्टि नहीं हुई है। आईएफएमआईएस पोर्टल पर एक्जिट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वेतन नहीं निकाला जा रहा है।

अफसरों ने कहा- डेटा एनालिसिस से पकड़ी गड़बड़ी- मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि ये कर्मचारियों के डेटा एनालिसिस की नियमित प्रक्रिया है। इन कर्मचारियों के खातों में वेतन की राशि नहीं जा रही है। ये एक प्रकार से किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने की दिशा में विभाग का ही प्रयास है।

विभागीय अफसरों की मानें तो इनमें 40 हजार नियमित कर्मचारी और 10 हजार अस्थाई कर्मचारी हैं। औसतन वेतन के हिसाब से माना जाए तो 5-6 महीनों में इन कर्मचारियों के वेतन के करीब 230 करोड़ रुपए अटके हुए हैं।

सिंघार बोले-सरकारी खातों में भूत ने आधार लिंक करवाया- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर इस मामले को लेकर लिखा- मध्यप्रदेश में 'भूत' भी सरकारी कर्मचारी। राज्य के लगभग 50,000 कर्मचारियों की सैलरी पिछले 5-6 महीनों से ट्रेजरी से नहीं निकाली गई।

सुनियोजित एवं एकीकृत प्रयास से मध्यप्रदेश पर्यटन क्षेत्र में असीम क्षमता और निवेश का बना आकर्षक केंद्र : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

ट्रेवल इंडिया टूरिज्म के नवीन भोपाल कार्यालय का किया शुभारंभ

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि किसी क्षेत्र में यदि औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और पर्यटन क्रांति आ जाये तो उस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। ऐसे क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजित होते हैं और बेरोज़गारी तथा गरीबी वहाँ ढूँढने से भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में अधोसंरचना विकास, पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण एवं प्रोत्साहन और पर्यटन क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ावा देकर सुनियोजित एवं एकीकृत प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से आज मध्यप्रदेश पर्यटन क्षेत्र में असीम क्षमता और निवेश का आकर्षक क्षेत्र बन गया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ट्रेवल एवं टूरिज्म के क्षेत्र में पिछले दो दशकों से सक्रिय ट्रेवल इंडिया टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के भोपाल स्थित नवीन कार्यालय का शुभारंभ किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अधोसंरचना विकास एयर अन्य आवश्यक प्रोत्साहनों के साथ ब्रांडिंग के लिए भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश की समृद्ध पर्यटन

धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने सतत जागरूकता गतिविधियाँ की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन के सांस्कृतिक, एडवेंचर, लेजर, धार्मिक, आध्यात्मिक, हेल्थ एंड वेलनेस, ग्रामीण, फ़िल्म आदि क्षेत्रों में आकर्षक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटक मध्यप्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, धरोहर स्थल, संस्कृति और सुविधाओं के प्रति जागरूक होंगे तब पर्यटन क्षेत्र में विकास को तेजी मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र की उपलब्ध संभावनाओं पर सशक्त प्रयास से देश ही नहीं, विदेशों से भी अधिकाधिक सैलानियों को आकर्षित करने में हम सफल होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नवीन संस्थान के शुभारंभ पर ट्रेवल इंडिया टूरिज्म प्रा. लि. के प्रतिनिधियों को शुभकामनाएँ दीं।

प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र में भी शासन विभिन्न मॉडल्स पर कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के लिए सब्सिडी एवं निवेश प्रोत्साहन की नीतियाँ लागू की गई हैं। भारत का हृदय स्थल मध्यप्रदेश पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। इसे शासन, प्रशासन, निवेशकों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नई ऊँचाइयों पर ले जाया जाएगा। ट्रेवल इंडिया टूरिज्म प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कंपनी की 20वीं वर्षगांठ में पल्लवी नगर में नवीन कार्यालय की स्थापना की गई है, जिससे पर्यटकों को और अधिक बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि नवीन कार्यालय के माध्यम से कंपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, कस्टमर-फ्रेंडली सेवाओं और नई योजनाओं के साथ एक नई शुरुआत कर रही है। पर्यटन, ट्रेवल एवं आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े विशिष्टजन, गणमान्य नागरिक एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एम्स भोपाल में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर जागरूकता अभियान का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनमानस को ब्रेन ट्यूमर, उसके लक्षणों, शीघ्र पहचान और उपचार विकल्पों के बारे में सटीक व वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना था। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जानकारीपरक सत्रों के माध्यम से ब्रेन ट्यूमर की प्रारंभिक पहचान, समय पर जांच और समुचित इलाज के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके साथ ही, आम लोगों के बीच व्याप्त भ्रांतियों और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए संवादात्मक सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिससे उपस्थित लोगों को अपने प्रश्न पूछने और संदेह दूर करने का अवसर मिला। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा कि भारत जैसे देश में, जहां न्यूरोलॉजिकल समस्याएं अक्सर समय रहते पहचानी नहीं जातीं, ब्रेन ट्यूमर के प्रति जनजागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। एम्स भोपाल न केवल जनजागरूकता को बढ़ावा देने में अग्रणी है, बल्कि जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी सतत रूप से समर्पित है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हमें समय पर जांच, अनुसंधान में निरंतर प्रगति और रोगियों के प्रति संवेदनशील उपचार की हमारी सामाजिक व चिकित्सकीय जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस जागरूकता अभियान में फैकल्टी सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, छात्रों तथा मरीजों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे कार्यक्रम न केवल प्रभावी रहा बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने में भी सफल रहा।

संपादकीय

भारत में घटती गरीबी!

अगर विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट को सही मानें तो भारत में गरीबी तेजी से घटी है खासकर मोदी राज में। विश्व बैंक की ये रिपोर्ट मोदी सरकार को राजनीतिक राहत देने वाली है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि देश में केवल अमीर और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब और गरीबतर होता जा रहा है तथा मोदी सरकार की नीतियां अमीर हितैषी हैं। खास बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश जैसे राज्य में गरीबी कम हो रही है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 11 वर्षों में अत्यधिक गरीबी को कम करने में जबरदस्त प्रगति की है। 2011-12 में देश की अत्यधिक गरीबी दर 27.1 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.3 प्रतिशत रह गई है। इसका मतलब है कि इस दौरान लगभग 269 मिलियन (26.9 करोड़) भारतीय गरीबी से बाहर निकल पाएं हैं। 2011-12 में देश में 344.47 मिलियन (34.4 करोड़) लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जबकि 2022-23 तक यह संख्या घटकर 75.24 मिलियन (7.5 करोड़) हो गई। गौरतलब है कि गरीबी रेखा का आकलन 3.00 डॉलर प्रतिदिन (2021 की कीमतों पर) के अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि इस बदलाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है। 2011-12 में इन पांच राज्यों में देश के 65 प्रतिशत अत्यधिक गरीब रहते थे। अब इन राज्यों ने गरीबी में कमी के दो-तिहाई हिस्से में योगदान दिया है। अगर पुराने मानक, यानी 2.15 डॉलर प्रतिदिन (2017 की कीमतों पर) की गरीबी रेखा से तुलना करें, तो 2011-12 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर 16.2 प्रतिशत थी, जो 2022 में घटकर सिर्फ 2.3 प्रतिशत रह गई। इस आधार पर 2011 में 205.93 मिलियन (20.5 करोड़) लोग इस सीमा से नीचे थे, जबकि 2022 में यह संख्या घटकर 33.66 मिलियन (3.36 करोड़) हो गई। रिपोर्ट के हवाले से एक और अहम बात यह है कि देश में ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों में गरीबी तेजी से कम हुई है। ग्रामीण भारत में अत्यधिक गरीबी दर 18.4 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई, और शहरी क्षेत्रों में यह 10.7 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 1.1 प्रतिशत रह गई है। भारत ने बहुआयामी गरीबी के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया है। 2005-06 में देश की 53.8 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी में थी, जो 2019-21 में घटकर 16.4 प्रतिशत और 2022-23 में और गिरकर 15.5 प्रतिशत रह गई। जाहिर है कि मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को भुनाने में देरी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को सरकार की गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशन और पारदर्शिता पर ध्यान देते हुए कई योजनाएं शुरू कीं जिनका सीधा लाभ गरीबों को मिला। पीएम आवास योजना से लोगों को घर मिले, उज्ज्वला योजना से स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन, जन धन योजना से बैंक खाते, और आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), डिजिटल सेवाओं और ग्रामीण विकास से जुड़े कामों ने भी गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इन सभी प्रयासों से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। यह उपलब्धि भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस रिपोर्ट का अर्थ यह भी नहीं है कि देश में अब गरीबी और बेकारी खत्म हो गई है, लेकिन उसमें कमी आई है, यह संतोष का विषय है। लेकिन विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होगी, जब देश पूर्णतः गरीबी से मुक्त होगा।

भारत- आत्म बल से आगे बढ़ता राष्ट्र

नजरिया

प्रो. महेश चंद गुप्ता
लेखक दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के को-ऑर्डिनेटर हैं।

भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक पहचान देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा क्षमता को दुनिया के सामने एक बार फिर मजबूती से प्रस्तुत किया है। संदेश स्पष्ट है कि भारत अपनी ताकत का प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करता है लेकिन जब करता है तो पूरी सटीकता और सफलता के साथ करता है। इस अभियान के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें भारत की ओर टिक गई हैं। अमेरिका और चीन जैसे वैश्विक शक्ति केंद्रों को अब यह समझ आने लगा है कि भारत केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक संभावित नेतृत्वकर्ता राष्ट्र है जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहा है।

भारत ने हाल ही में जिस 'ऑपरेशन सिंदूर' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक सोच, वैश्विक दृष्टिकोण और राष्ट्र की सामूहिक ताकत का प्रतीक बन गया है। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारत को एक बार फिर यह साबित करने का मौका दिया कि वह केवल एक बड़ी जनसंख्या या पुरातन संस्कृति वाला देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति भी है जो वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। भारत अब आत्म बल से आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है।

भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक पहचान देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा क्षमता को दुनिया के सामने एक बार फिर मजबूती से प्रस्तुत किया है। संदेश स्पष्ट है कि भारत अपनी ताकत का प्रयोग केवल आवश्यकता पडने् पर करता है लेकिन जब करता है तो पूरी सटीकता और सफलता के साथ करता है। इस अभियान के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें भारत की ओर टिक गई हैं। अमेरिका और चीन जैसे वैश्विक शक्ति केंद्रों को अब यह समझ आने लगा है कि भारत केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक संभावित नेतृत्वकर्ता राष्ट्र है जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहा है।

भारत की सोच केवल अमेरिका या चीन की बराबरी करने की नहीं है बल्कि उनसे आगे निकलने और विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने की है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे रोचक बात यह रही कि इससे भारतीय राजनीति में भी एक नई चेतना का संचार हुआ। ओवैसी और शशि थरूर जैसे जो नेता पहले सरकार विरोधी माने जाते थे, उन्होंने भी इस ऑपरेशन की सराहना की और राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना। इन नेताओं ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में विश्व के विभिन्न देशों में जा कर जिस मजबूती से भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान को बेनकाब किया है, उससे यह स्पष्ट हुआ कि जब बात देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा की होती है, तो राजनीतिक मतभेद पीछे छूट जाते हैं और 'भारत पहले' की भावना सर्वोपरि हो जाती है।

यह राष्ट्रवाद का वही रूप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक से भारतीय जनमानस में गहराता गया है। 2014 से जो राष्ट्र निर्माण की लहर शुरू हुई, वह अब स्पष्ट परिणाम देने लगी है।

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने उसे वैश्विक निवेश और तकनीकी साझेदारी का केंद्र बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ–साथ भारत ने तकनीकी मोर्चे पर भी बड़ी

उपलब्धियां हासिल की हैं।

कश्मीर में बना चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कौशल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आश्चर्यजनक नमूना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज के साथ श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर लंबे अरसे से देखे जा रहे सपने को साकार कर दिया है। इसी के साथ कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गया है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी ट्रेन यात्रा संभव हो सकेगी। यह जम्मू और कश्मीर के डोगरा राजा महाराजा प्रताप सिंह का सपना था, जिन्होंने 1880 के दशक के अंत में इस मार्ग की कल्पना की थी और सर्वेक्षण के लिए ब्रिटिश इंजीनियरों को लगाया था। कश्मीर घाटी के लोगों के लिए ये ट्रेन न सिर्फ हर मौसम में आने–जाने के लिए एक भरोसेमंद साधन बन गई है बल्कि इससे इलाके में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। इससे पहले अप्रैल में मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन सी ब्रिज का उद्घाटन किया था। समुद्र के ऊपर बना यह रेलवे ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ता है।

भारत में अब राफेल लड़ाकू विमानों के मुख्य ढांचे का निर्माण हैदराबाद में किया जाएगा जो कि 'मेक इन इंडिया' पहल की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बीच हुआ एग्रीमेंट बताता है कि अब भारत केवल आयातक नहीं बल्कि रक्षा उत्पादों का निर्माता और निर्यातक भी बन रहा है। भारत अब हथियारों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता और निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। रक्षा उत्पादन में भारत का भविष्य बेहद उज्ज्वल है।

रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की बड़ी उपलब्धि है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश देने की नीति अपनाकर एक बड़ा बदलाव किया है। इससे प्रतिस्पर्धा, नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा मिला है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित हुई ब्रह्मोस मिसाइल की ऑपरेशन सिंदूर के विश्व बाजार में मांग बढ़ी है और कई देश अब भारत से रक्षा उपकरण खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।

उम्मीद है, भारत अगले दस वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ देगा। इतना ही नहीं, स्वदेशी तकनीक और स्टार्टअप्स के जरिए भारत अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है।

भारत ने सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी बन रहा है। सरकार की योजनाओं और प्राइवेट निवेश के समन्वय से भारत अब ऊर्जा निर्यातक देश बनने की राह पर है।

अब भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण शुरू हो चुका है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सबसे अहम हिस्सा है। अब भारत में इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता मिलेगी।

भारत की विदेश नीति अब केवल अपने हितों तक सीमित नहीं रही बल्कि दुनिया को साथ लेकर चलने की नीति पर केन्द्रीत है। प्रधानमंत्री मोदी का यह स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि भारत वैश्विक नेतृत्व में केवल भागीदार नहीं बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभाना चाहता है। जी 20 की अध्यक्षता, वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला परिदृश्य इस बात के संकेत हैं कि भारत अब एक संतुलनकारी शक्ति बनकर उभर रहा है।

हालांकि भारत की प्रगति उल्लेखनीय है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए भारत आगे बढने् को दृढ़ संकल्पित है। समग्र विकास और समग्र क्रांति की सोच वाले भारत की नीति अब स्पष्ट है।

2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना केवल एक राजनीतिक घोषणापत्र नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। इसके लिए नीति, नियत और नागरिक तीनों का सहयोग आवश्यक है और यही तीनों आज एकजुट होकर भारत को आगे ले जा रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता को दिखाने के साथ–साथ एक संदेश भी दिया है कि भारत अब अपने हितों को लेकर संकोच नहीं करता। वह शांति चाहता है, लेकिन किसी भी हस्तक्षेप या चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। भारत अब उस मुकाम पर है जहां से वह केवल अपनी समस्याएं ही नहीं सुलझा रहा बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी भागीदारी निभा रहा है। यही है नया भारत, जो आत्मनिर्भर, शक्तिशाली, तकनीकी रूप से उन्नत, और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने को तत्पर है। यह उस नये भारत की झलक है जो आत्म विश्वास, एकता, नवाचार और नेतृत्व की भावना से परिपूर्ण है।

मीडिया की विश्वसनीयता पर उठते सवाल

मुद्दा

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
लेखक स्तंभकार हैं।

मीडिया की विश्वसनीयता पर उठते सवालों के बीच आकाशवाणी और बाद में दूरदर्शन के शुरुआती वे दिन बरबस याद आ जाते हैं जब आकाशवाणी के नेशनल और प्रादेशिक समाचारों के प्रति आमजन के विश्वास को इसी से समझा जा सकता है कि चौराहों की चाय-पान की दुकानों पर खड़े होकर भी समाचार सुनने में किसी को कोई संकोच ना होकर गर्व महसूस होता था। आकाशवाणी के नेशनल समाचारों की बात हो तो सुबह 8 बजे और रातः पौने नो बजे के समाचार बुलेटिनों की बेसब्री से प्रतीक्षा होती थी तो प्रातःकालीन प्रादेशिक समाचार के साथ ही खासतौर से सायंकालीन सात बजे के प्रादेशिक समाचार को कोई भी प्रदेषवासी मिस नहीं करना चाहता था। आकाशवाणी और दूरदर्शन का यह स्वर्णकाल इस मायने में कहा जा सकता है कि सरकारी नियंत्रण में होने के बावजूद आमआदमी तो क्या पक्ष और विपक्ष के नेतागण भी समाचारों की विश्वसनीयता पर प्रष्न नहीं उठा पाते थे। होता तो यहां तक था कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों से लोग अपनी घड़ियों को मिलाया करते थे। विश्वसनीयता का यह कोई आसान काम नहीं था पर उस समय के दिग्गज मीडियाकर्मियों ने अपनी मेहनत, लगन और निष्पक्षता से सींचने का काम किया और उसका परिणाम यह रहा कि उस समय के मीडिया दिग्गजों को समूचे समाज में चाहे वह राजनीतिक स्तर हो, ब्यूरोक्रेटिक स्तर हो या फिर आमजन सभी जगह सम्मान से देखा जाता था। यदि प्रादेशिक स्तर की बात की जाए तो आकाशवाणी जयपुर अजमेर के समाचार संपादक और बादमें दूरदर्शन जयपुर केन्द्र के समाचार एकांश के निदेशक मोहनराज सिंघवी जिन्हे मीडिया जगत में एमआर सिंघवी के नाम से जाना जाता रहा है की मेहनत, निष्पक्षता और मीडिया की स्वतंत्रता की पक्षधरता का ही परिणाम रहा कि मीडिया जगत में एमआर सिंघवी एक ब्राण्ड के नाम से पहचान बनाने में कामयाब रहे। पक्ष-विपक्ष के सभी नेता, समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों सहित आमजन में जिस तरह की छवि एमआर सिंघवी की बनी वह आज के मीडिया कर्मियों के लिए ईर्च्छा का कारण बन सकती है तो प्रेरणास्पद भी है। बात में इतना दम की क्या तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीमण्डल के सदस्यगण और क्या ब्यूरोक्रेसी के कर्ताधर्ता एमआर सिंघवी की बात को कमतर समझने की भूल भी नहीं कर सकते थे।

यह आज के समय में अविश्वसनीय कल्पना ही हो सकती है कि 90 के दशक में एमआर सिंघवी के आकाशवाणी जयपुर पिंकसिटी पेट्रोल पंप के पास स्थित आवास पर मिलनेवाले जरुरतमंद लोगों का जमावड़ा इस तरह से लगा रहता था जैसे किसी राजनेता के निवास पर लगा होता था। पीड़ित व्यक्ति के लिए एमआर सिंघवी एक सहारा रहे हैं। इसका कारण भी यह रहा कि यदि काम जायज है और हितकारक है तो सिंघवी जी आने वाले व्यक्ति के सामने ही संबंधित मंत्री से लेकर अधिकारी को फोन करने में किसी तरह का संकोच नहीं करते थे और आने वाले व्यक्ति की आंखें एहसान से बोझिल हो जाती तो काम भी आसानी से हो जाता था। खासबात यह कि बिना जान-पहचान भी कोई अपने दुख-दर्द को लेकर पहुंच जाता था तो सहयोग करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ते। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। किसी दिन आकाशवाणी के अनुबंध पर समाचार अनुभाग के लिए लिखित परीक्षा हुई और एक दिन एकाएक घर पर आकाशवाणी से अनुबंध का पत्र आ गया। डिप्लोमा भले ही पत्रकारिता में कर लिया हो पर अनुभव के मामलें में शून्य होने के बावजूद जिस तरह से सिंघवी जी ने मेरे जैसे को तराशा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मजे की बात यह कि एमआर सिंघवी पोलियों से ग्रसित होने के कारण चलने फिरने में असुविधा के बावजूद किसी के भी सहयोग के लिए उनके साथ जाने को तैयार हो जाते। विकलांगों के लिए उन्होंने संघर्ष करने के साथ ही स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के खेलों का आयोजन, संयोजन व प्रोत्साहन दिया। देवेन्द्र झाझड़िया तो एक उदाहरण मात्र है जिन्हें विश्वपटल पर पहचान सिंघवी जी की प्रेरणा-प्रोत्साहन और सहयोग से ही संभव हो सका।

आकाशवाणी का यह वह जमाना था जब टेलीप्रिंटर और टेलीफोन ही प्रमुख माध्यम होते थे। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से समाचारों की डाक आती थी वहीं प्रादेशिक समाचारों में समूचे प्रदेश के प्रमुख समाचारों का समावेश महत्वपूर्ण होता था। ऐसे में लगभग प्रतिदिन समाचार संपादक होने के बावजूद बिना किसी संकोच के फोन से समाचार लेने व स्वयं लिखने तक में संकोच नहीं करने के कारण ही मीडिया जगत में पहचान और विश्वसनीयता बनी। बुलेटिन में खबरों के चयन से लेकर प्रसारण तक तनावरहित वातावरण में काम करना और नए लोगों को प्रोत्साहित करना यही तो सिंघवी जी की पहचान रही। हिम्मत यह कि जयपुर दूरदर्शन निदेशक समाचार रहते हुए तत्कालीन केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्व. गिरिजा व्यास के जयपुर में एक ब्यूटीपार्लर के उद्घाटन के समाचार प्रसारित करने के दबाव के बावजूद मीडिया मानदंडों के विरुद्ध बताते हुए प्रसारित नहीं करना सिंघवी जैसे बिड़ला ही कर सकते हैं। इसी तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाडिया के पिताजी के देहावसन के समाचार प्रसारण के लिए लाख दबाव के बावजूद विनम्रता से नीति विरुद्ध जाकर समाचार प्रसारित नहीं करने का निर्णय कोई सिंघवी जैसा ही ले सकता है। आज तो केन्द्रीय मंत्री वो भी स्वयं का माईबाप यानी कि स्वयं के विभाग का हो तो उसकी खबर तो क्या आगे पीछे सेवा सुश्रुषा में ही लगे रहने में गर्व महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एमआर सिंघवी कोई ऐसे ही नहीं बनता, कोई ऐसे ही राजनेताओं, पक्ष विपक्ष के छोटे से लेकर बड़े नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स सभी के लिए सम्मानजनक अपनी कार्यशैली, निष्पक्षता, निष्ठा और मेहनत से ही बना पाता है। प्रदेश का संभवतः कोई छोटा-बड़ा नेता या अधिकारी ऐसा नहीं होगा जो एमआर सिंघवी के नाम, पहचान और उनकी कार्यशैली का कायल नहीं होगा। इतने विस्तृत केनवास पर पहचान और विश्वसनीयता कोई ऐसे नहीं बन जाती बल्कि यह ईमानदारी, निस्वार्थता और सहायता और सहयोग की भावना के कारण ही हो पाता है। यही सिंघवी जी की पूंजी मानी जा सकती है। समाचार में समाचारत्व है तो उसे बिना किसी पक्षपात के स्थान मिलता वहीं तत्कालीन राज्यपाल जोगेन्द्र सिंह द्वारा रिकार्ड वाइस ओवर प्रसारित कराने के दबाव के बावजूद स्तरीय नहीं होने से प्रसारित नहीं करने का साहस कोई एमआर सिंघवी ही कर सकता है।

यह सब इसलिए कि आज मीडिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। खासतौर से इलेक्ट्रोनिक चैनलों की विश्वसनीयता पूरी तरह से दाव पर लग चुकी है। चैनलों पर बेसिरफेर की चर्चा और आरोप-प्रत्यारोप का मंच बनना आज आम हो गया है। रही सही कसर सोशियल मीडिया ने कर दी है जहां अपलोड सामग्री भ्रम पैदा करने का काम करने के साथ ही उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ी कर देती है यही कारण है कि चैनलों पर समाचार प्रसारित होते समय वीडियो की विश्वसनीयता पर स्वयं चैनल द्वारा सवाल खड़े किया जाना आम है। होना तो यह चाहिए कि जब तक समाचार संपादक स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक केवल टीआरपी के चक्कर में ऐसे समाचार व वीडियो को प्रसारित ही नहीं करना चाहिएं। क्योंकि यह सवाल दर्शकों के विश्वास को बनाए रखने का हो जाता है। एक समय था जब कोई भी बड़ी घटना हो जाती थी तो लोग आकाशवाणी के आगामी समाचार बुलेटिन पर कान लगाकर पुष्टि होने पर ही विश्वास करते थे। आज अपुष्ट समाचार आम होते जा रहे हैं। आकाशवाणी के पुराने दिनों और एमआर सिंघवी जैसे व्यक्तित्व व संपादकों के बहाने आज मीडिया की विश्वसनीयता का वहीं पुराना युग देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रसारित समाचार की विश्वसनीयता पर कोई सवाल उठता है तो फिर यह मीडिया के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होना चाहिए। मीडिया जगत को आज एमआर सिंघवी जैसे मीडिया दिग्गज की आवश्यकता महसूस हो रही है ताकि मीडिया चाहे इलेक्ट्रोनिक हो या प्रिंट उस पर प्रसारित या प्रकाशित समाचार को वेदवाक्य की तरह विश्वसनीय माना जाए। बदलते हालात में आज यह आवश्यकता अधिक हो गई है क्योंकि समाज आज भ्रमित अधिक हो रहा है तो मीडिया और सोशियल मीडिया ने विश्वसनीयता को ही प्रष्नों के घेरे में खड़ा कर दिया है। समाचार पर प्रश्न उठने की कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए।

चिनाब ब्रिज से मुख्यधारा में कश्मीर

कश्मीर रेल लिंक

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'
लेखक प्रोफेसर हैं।

जब कश्मीर की हवाओं में रेल की पहली सीटी गूंजी, तो यह मात्र ध्वनि नहीं, बल्कि एक नए भारत की उद्घोषणा थी—एक ऐसा क्षण जब घाटी की गोद में बसे स्वर्ग को रेल की पटरियों ने आलिंगनबद्ध कर लिया। चिनाब नदी पर खड़ा दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल—चिनाब ब्रिज—जो एफिल टॉवर को भी पीछे छोड़ता है, केवल एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि भारत की आत्मशक्ति और संकल्प की मूर्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर तक पहली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर इतिहास रचा—यह एक गाड़ी का प्रस्थान नहीं, बल्कि विकास की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाला अलौकिक पल था। मोदी सरकार की दूरदर्शिता और अथक मेहनत ने इस असंभव सपने को साकार कर दिखाया, जो न केवल कश्मीर को जोड़ता है, बल्कि पूरे विश्व को भारत की शक्ति का दर्पण दिखाता है। यह एक ऐसी विजय है जो हिमालय की चोटियों से लेकर घाटी की वादियों तक गूंज रही है, और मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व ने इसे अमर बना दिया है।

दशकों तक भौगोलिक बाधाओं से जूझते कश्मीर को अब रेल नेटवर्क ने अपने आगोश में ले लिया है। पहले सड़क मार्ग का जोखिमभरा, थकाऊ और असुरक्षित सफर अब वंदेभारत जैसी अत्याधुनिक रेलगाड़ियों से मात्र 10 घंटे से भी कम में पूरा होगा। कटरा से बनिहाल होकर श्रीनगर तक यह यात्रा न केवल समय और श्रम बचाएगी, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक नई सुबह लाएगी। आईआरसीटीसी की विश्वस्तरीय सुविधाएँ—सुविधाजनक टिकट बुकिंग, आधुनिक कोच, और स्वादिष्ट खानपान—इस सफर को एक यादगार अनुभव में बदल देंगी। प्रधानमंत्री के शब्दों में, यह पुल लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि दिलों का सेतु है, जो आतंक की परछाइयों को मिटाकर शांति और समृद्धि की किरणें बिखेर रहा है। हाल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने जिस दृढ़ता और साहस के साथ जवाब दिया, उसने साफ संदेश दिया—पाकिस्तान का भय फैलाने का मंसूबा विफल होगा, भारत अब केवल सहन नहीं करता, वह विजय की राह बनाता है।

यह रेल नेटवर्क आर्थिक क्रांति का आधार बनने जा रहा है। कश्मीर के लाल सेब, हस्तशिल्प, और पारंपरिक उत्पाद अब कम लागत और कम समय में देश के बड़े बाजारों तक पहुँचेंगे, स्थानीय व्यापारियों को समृद्धि और युवाओं को रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। यह परिवर्तन कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा, जहाँ हर घर में खुशहाली की किरणें पहुँचेंगी। पर्यटन के लिए यह कनेक्टिविटी एक स्वर्णिम युग का सूत्रपात है। भारत के कोने-कोने से लोग अब रेल से सीधे कश्मीर की मनोरम वादियों में कदम रख सकेंगे—जहाँ हिमालय की गोद में खिले चिनार, डल झील की शांति, और शालीमार बाग का सौंदर्य रेल की खिड़की से नजर आएगा। जो यात्री कठिन यात्रा से कतराते थे, उनके सपनों को पंख लगेंगे, और कश्मीर पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनेगा—यह सब संभव हुआ है मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प और तकनीकी प्रगति के बल पर। यह रेललाइन केवल पटरियों का जाल नहीं, बल्कि एकता, विश्वास, और प्रगति की अनुपम गाथा है। कश्मीर, जो कभी देश की मुख्यधारा से कटा हुआ लगता था, अब उसका धड़कता दिल बन रहा है। पटरियों की गूंज, रेल की सीटी, और घाटी की हवाओं में यह नवनिर्माण की पुकार है, जो भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर कर रही है। यह परियोजना न केवल कश्मीर को समृद्ध करेगी, बल्कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगी। मोदी सरकार की इस अप्रतिम उपलब्धि ने कश्मीर को नई पहचान दी है—एक ऐसी पहचान जो आतंक के अंधेरे को चीरकर विकास की रोशनी फैलाएगी।

जब रेल कश्मीर की वादियों में दौड़ेगी, तो यह केवल एक गाड़ी नहीं, बल्कि हर उस सपने का प्रतीक होगी जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर घाटी के हर गाँव तक पहुँचना चाहता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो दिलों को छूती है, आँखों में आशा के आँसू लाती है, और भारत की आत्मा को गर्व से भर देती है। मोदी सरकार की इस अलौकिक विजय ने कश्मीर को समृद्धि का रास्ता दिखाया है, और यह रेलमार्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा—एक ऐसी प्रेरणा जो अनंत काल तक गूंजेगी, जब तक हिमालय खड़ा है और कश्मीर की वादियाँ हरी-भरी हैं। यह भारत की विजय का गान है, जो हर दिल में बस जाएगा और हर आत्मा को प्रेरित करेगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अपने विकास की बात सुन रो पड़े चौराहा और उपवन

व्यंग्य

नंदकिशोर बर्वे
लेखक व्यंग्यकार हैं।

उस शहर में कई चौराहे थे . और उपवन भी . जो प्रकृति ने उसे उपहार स्वरूप दिए थे , या परिस्थितिवश विकसित हो गये थे . वे सब अपने हिसाब से अपना जीवन गुजार रहे थे . एक दिन सरकार ने घोषणा की कि चौराहों और उपवन का 'विकास' किया जायेगा . बस उसी दिन से वे चिंतित हो चले हैं . दिन रात बैचेन रहते हैं .

जिस चौराहे के विकास की चर्चा चल रही थी, उसने अपने सगे भाई, पास वाले चौराहे का विकास खुद रूबरू देखा था. उसका ऐसा मानना था, कि जैसे ही विकास की शुरुआत होती है उसके पहले चरण में पेड़ पौधों का विनाश होता है. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि विकास की पहली शर्त विनाश होती है . विकास और विनाश की नाम राशी चाहे एक ही हो, लेकिन उनकी फ़ितरत सूरत और सीरत में बड़ा फर्क होता है . अब होने को तो राम -रावण , कृष्ण-कंस, एक ही राशी के थे, पर देख लो बानगी सामने है .

तो बात यह है कि अपने विकास की बात सुन रो पड़ा चौराहा . मैं उधर से गुजरा तो उसका उतरा चेहरा देख उसके हाल चाल जानने को रुक गया. वह भी हरी बत्ती में ! जहाँ लोग लाल बत्ती में रुकना अपनी बेइज्जती समझते हों , वहाँ ग्रीन सिगनल पर रुकना गाली खाने की पूरी गारंटी होती है .

क्या बात हैं भाई आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हो ? मैंने पूछा . हाँ यार बात ही ऐसी है . आज का पेपर नहीं पढ़ा ? अब मेरे विकास की बारी है . उसकी उदासी और गहन हो गई .

अच्छा यह तो अच्छी बात है . मैंने कहा .

अच्छा ! इसमें क्या अच्छा दिखा रहा आपको ? जिन पेड़ों की छाया में लाल बत्ती के वक्त सुस्ताते हो वही सबसे पहले बलि चढ़ेंगे इस विकास की . पहले छायादार पेड़ों को काटो फिर छाया करने के कृत्रिम तरीके तलाशो . वो भी जानलेवा !

तुम्हारी बार गलत भी नहीं है, पर दिनों दिन वाहनों की तादात देख रहे हो . उनको कहाँ धरें किधर से गुजारें ? मैंने अपना तर्क दिया . हाँ वाहन धरे तो जायेंगे हमारी छाती पर ही. पर तुम लोगों का परंपरागत दया भाव कहाँ गया ? शांति पूर्ण सह अस्तित्व की बातें तो खूब होती हैं. पर सिर्फ अपने अस्तित्व की ही चिंता करते हो तुम लोग. चौराहे का आक्रोश फट पड़ा.

फिर तुम ही कोई रास्ता सुझाओ भाई. मुझे उसके आगे कोई तर्क नहीं सुझा .

अरे यह तो वही बात हुई कि हमारा सर काटने के लिए हमीं से तलवार मांगी जा रही है. करना ही है तो फ़क्त इतना ही कर दो हमें अपने हाल पर छोड़ दो. हम खुद की भी बचा लेंगे और तुम्हारे पर्यावरण को भी. जिसकी चर्चा तो तुम लोग बहुत करते हो . पर चिंता बिल्कुल नहीं करते.

अपनी इतनी बेइज्जती (?!) के बाद मैं भी वहां रुकता भी तो कैसे ? सो छूटा और भागा. आगे बढ़ते ही उस उपवन ने रास्ता रोक लिया जिसके भी विकास की घोषणा हुई थी. मैंने देखा सारे वन वनस्पति एकदम असीम उदासी ओढ़े खड़े थे. मैं उनको देखते ही सहम भी गया और समझ भी गया की 'विकास' की बयार की सूचना यहाँ भी पहुँच चुकी है. मेरी हिम्मत नहीं थी कि किसी पेड़ पौधे तो ठीक घास फूस से भी आँख मिला पाता . फिर भी मैं बेबस सा रुक गया.

तो आप तक भी खबर आ गई लगता है? मैंने पूछा.

हाँ ! उसने दीर्घ निःश्वास के साथ संक्षित उत्तर दिया.

मौन तो हो ही .अब चुप भी हो गये.

मैं आपकी पीड़ा में सहभागी हूँ. मैं इतना ही कह पाया.

सहभागी मत बनो. सहयोगी बनो. चलो चलते हैं वहीं जिनके कारण संकट है. क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा. यह उसका आर्त्तनाद था.

लेकिन...

लेकिन वेकिन बाद में कर लेना. अभी ही समय है , कुछ करने और खुद को बचाने का. एक बार कुल्हाड़ी हाथ आ गई, तो फिर कुच्छ नहीं हो सकेगा. तुम मेरे साथ होने का दावा करते हो ना . बस तुम मेरे साथ चलो केवल खड़े रहना. अपनी गुहार मैं खुद लगा लूँगा. इस उम्मीद से कि ऐसा विकास रुक जाये, जो सबसे पहले पर्यावरण को उजाड़ता है. 'सरकार' यदि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल देना चाहती होगी, तो सुनेगी जरुर. जल्दी चलो कहीं देर ना हो जाये .

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति के तीखे सवाल और समाधान

संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय को अब संदर्भ का उत्तर देने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करना होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से इस पर राय मांगी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है?

अभी कुछ समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की, जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई। उप-राष्ट्रपति, सांसदों एवं राजनेताओं ने इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। एक दुर्लभ कदम के तहत, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा इस पर सर्वोच्च न्यायालय से इस पर राय मांगी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है? संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय को अब संदर्भ का उत्तर देने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया था कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए उसके द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में मान ली गई सहमति होगी। संदर्भ में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की मान ली गई सहमति की अवधारणा संवैधानिक योजना से अलग है और राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को मौलिक रूप से सीमित करती है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए 14 तीखे सवाल भेजे। इसमें इस बात पर जोर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201, जो राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, कोई समय-सीमा या विशिष्ट प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ निर्धारित नहीं करते हैं।

राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए उनमें पहला सवाल यह है कि जब राज्यपाल के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या हैं? दुसरा प्रश्न जब राज्यपाल के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या वह अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? चौथा प्रश्न, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? पांचवा प्रश्न संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है?

अन्य प्रश्नों में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? संवैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय-सीमाएँ लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में, क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति या अन्यथा के लिए विधेयक को आरक्षित करने पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है?

इसके अलावा यह भी राय मांगी गई है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं ? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक की सामग्री पर, किसी भी तरह से, कानून बनने से पहले न्यायिक निर्णय लेना अनुमेय है? साथ ही क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग तथा राष्ट्रपतिध्राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरीके से प्रतिस्थापित किया जा सकता है ? इसके अलावा यह भी शामिल है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू कानून है?

राष्ट्रपति द्वारा यह भी पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करे ? यह भी संदर्भित किया गया है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने/आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत हैं? इसके अलावा यह भी राय मांगी गई है कि क्या संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है?

अप्रैल में एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समय सीमा निर्धारित की थी जिसके भीतर राज्यपाल को राज्य विधानसभाओं द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर कार्रवाई करनी होगी। न्यायालय ने कहा था कि इस समय सीमा का पालन न करने पर

न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि हालांकि अनुच्छेद 200 के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रावधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि राज्यपाल को विधेयकों के स्वीकृति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कार्रवाई न करने की अनुमति मिल जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों का निर्वहन न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर विधेयकों पर निर्णय लेना आवश्यक है और इस अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण दर्ज करके संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक मामले में पारित फैसले की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई लोगों ने आलोचना की थी। संविधान का अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकें। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की यह राय बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व काफी अधिक होता है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत इस तरह की राय कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति ने यह संदर्भ 13 मई को भेजा, जिसमें कुल 14 कानूनी प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों में न केवल विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, बल्कि यह भी पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को खुद यह पहले तय करना चाहिए या नहीं कि कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है, जिससे उसे बड़ी पीठ को सौंपा जा सके। एक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति की सीमाओं को लेकर भी है। वहीं, अंतिम प्रश्न केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की मूल सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित है कि क्या यह सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है या अन्य अदालतों के पास भी?

इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में राय देने से इंकार किया है। सन् 1993 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में जब मंदिर की पूर्व स्थिति पर राय मांगी गई थी, तब न्यायालय ने धार्मिक और संवैधानिक मूल्यों का हवाला देते हुए मना कर दिया था। सन् 1982 में पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास से संबंधित एक कानून पर राय मांगी गई थी, लेकिन कानून पारित हो जाने और उस पर याचिकाएं दायर हो जाने से राय अप्रासंगिक हो गई थी। इस बार के मामले को लेकर यह आशंका भी उठी है कि कहीं राष्ट्रपति (सरकार) पहले से दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटना तो नहीं चाहतीं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय पहले स्पष्ट कर चुका है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई राय किसी न्यायिक निर्णय की समीक्षा या उसे पलटने का जरिया नहीं बन सकती। सन् 1991 में कावेरी जल विवाद में न्यायालय ने कहा था कि पहले दिए गए निर्णय पर दोबारा राय मांगना न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है।

संपूर्ण विवाद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन की बहस को फिर से सामने लाता है। विपक्ष-शासित राज्यों में विधेयकों को राज्यपालों द्वारा लंबे समय तक रोककर रखने या अस्वीकार करने की घटनाओं से यह मुद्दा गरमाया है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऐसे 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को केंद्र और राज्य के संबंधों में असंतुलन बताया और समय सीमा जरूरी ठहराई। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को कार्यपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया। अब देखना यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस संवैधानिक मुद्दे पर क्या राय देता है और यह राय केंद्र-राज्य संबंधों और संविधान की व्याख्या को किस दिशा में ले जाएगी।

हिन्दू साम्राज्य दिवस

लोकेन्द्र सिंह

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।

भारत के स्वराज्य की हुंकार

छत्रपति शिवाजी महाराज भारत की स्वतंत्रता के महान नायक हैं, जिन्होंने 'स्वराज्य' के लिए संगठित होना, लड़ना और जीतना सिखाया। मुगलों के लंबे शासन और अत्याचारों के कारण भारत का मूल समाज आत्मदैन्य की स्थिति में चला गया था। विशाल भारत के किसी न किसी भू-भाग पर मुगलों के शोषणकारी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष तो चल रहा था लेकिन उन संघर्षों से बहुत उम्मीद नहीं थी। भारत के वीर सपूत अपने प्राणों की बाजी तो लगा रहे थे लेकिन समाज को जागृत और संगठित करने का काम नहीं कर पा रहे थे। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के भीतर विश्वास जगाया कि हम मुगलों के शासन को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं, यदि सब एकजुट हो जाएं। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देवलोकगमन के बाद भी 'हिन्दवी स्वराज्य' का विचार पल्लवित, पुष्पित और विस्तारित होता रहा। 'हिन्दू साम्राज्य दिवस' या 'श्रीशिव राज्याभिषेक दिवस' भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने दुनिया को बताया कि भारत के भाग्य विधाता मुगल नहीं हैं। भारत का हिन्दू समाज ही भारत का भाग्य विधाता है। भारत में हिन्दुओं का राज्य है। उनके शासन का नाम है- 'हिन्दवी स्वराज्य'।

विक्रम संवत् 1731, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को स्वराज्य के प्रणेता एवं महान हिन्दू राजा श्रीशिव छत्रपति के राज्याभिषेक और हिन्दू पद पादशाही की स्थापना से भारतीय इतिहास को नयी दिशा मिली। दासता के घोर अंधकार में स्वराज्य की एक चमकदार रोशनी था- हिन्दवी स्वराज्य। हिन्दू साम्राज्य दिवस को हम भारत के स्वराज्य की हुंकार भी कह सकते हैं, जब हिन्दुओं ने आत्मविश्वास से सीना ठोंककर मुगलों को ललकारा और कहा कि भारत में एक बार फिर स्वराज्य की स्थापना हो गई है, जिसमें सबका कल्याण है। अनेक इतिहासकार एवं विद्वान कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना न की होती, तो भारत का इतिहास कुछ और होता।

यह अतिश्योक्तिपूर्ण विचार नहीं है। अपितु भारत के पड़ोसी देशों एवं दूर-दराज के उन देशों की स्थिति को देखकर सहज कल्पना की जा सकती हैं, जहाँ मूल समाज की अपेक्षा बाहरी आक्रांताओं का शासन स्थायी हो गया। ऐसे देशों में वहाँ के मूल समाज की संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि जिस प्रकार के अत्याचार मुगल शासक भारत में कर रहे थे, उसके बाद हिन्दू समाज किस स्थिति को प्राप्त होता। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार जीएस सरदेसाई ने लिखा है कि 'मुस्लिम शासन के अधीन पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। न कोई पूछताछ होती थी, न न्याय मिलता था। अधिकारी जो चाहें, वही करते थे। स्त्रियों के सम्मान का हनन, हत्याएं, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन, उनके मंदिरों का विध्वंस, गायों का वध- ऐसे घिनौने अत्याचार उस शासन में आम बात थे। निजामशाही ने तो खुलेआम जीजाबाई के पिता, उनके भाइयों और पुत्रों की हत्या कर दी थी। फलटन के बजाजी निंबालकर को जबरन मुसलमान बनाया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। हिंदू सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकते थे। यही बातें थीं, जिन्होंने शिवाजी के भीतर धर्मसम्मत क्रोध जगा दिया। विद्रोह की प्रबल भावना ने उनके मन को पूरी तरह घेर लिया। उन्होंने तुरंत कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिसके हाथ में शस्त्र की शक्ति है, उसे कोई भय नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं आती'। औरंगजेब का शासन तो हिन्दुओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं था।

मुगलों के अनीतिपूर्ण शासन के बरक्स छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य में लोकहित सर्वोपरि था। उन्होंने शासन को 'स्व' के आधार पर विकसित किया, इसलिए वह सबका अपना स्वराज्य था। महाराज ने राज्य के प्रत्येक तत्व यानी जल, जंगल, जमीन और जन के लिए नीतियां बनायीं। भारत की संस्कृति का संरक्षण किया। हिन्दू धर्म और उसके पवित्र स्थलों को प्राथमिकता दी। आज भी हम हिन्दू साम्राज्य को याद करते हैं, उसका कारण है कि वह सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 'शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे जिन्हें हम आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर सकते हैं। उनका उद्देश्य था अपने प्रजा को शांति देना, सभी जातियों और धर्मों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, एक कल्याणकारी, सक्रिय और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौसेना का विकास करना और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रशिक्षित सेना तैयार करना'। छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों पर चलकर हम आज भी एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह देखना सुखद है कि देश में ऐसी सरकार है, जो छत्रपति की स्वराज्य की अवधारणा में विश्वास करती है, उनको अपना आदर्श मानती है और उनके बनाए मार्ग पर चलने का प्रयास करती है।

रैगिंग

संध्या अग्रवाल

खत्म होना चाहिए यह अभिशाप

हाल ही में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। छात्र के स्वजनों का आरोप है कि रैगिंग के कारण उनके बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ी। इस घटना ने एक बार फिर से रैगिंग के मुद्दे को उजागर किया है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर छात्र के स्वजनों की बात सच है और सचमुच बच्चे की जान रैगिंग के कारण गई है, तो तत्काल रैगिंग पर रोक लगाने का समय आ गया है। अब किसी और घर का चिराग ना बुझे। अब और कोई बच्चा रैगिंग के चलते अवसाद में ना जाए, इसलिए रैगिंग बंद होना चाहिए। रैगिंग एक गंभीर समस्या है जो न केवल छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, बल्कि यह उनकी जान भी ले सकती है। रैगिंग के दौरान छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वे अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं।

रैगिंग के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है सीनियर्स द्वारा जूनियर्स को प्रताड़ित करने की मानसिकता। सीनियर्स अपने जूनियर्स को अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, जिससे वे अपनी दबंगई दिखा सकें। लेकिन यह दबंगई कई बार जानलेवा साबित होती है।

रैगिंग के प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। रैगिंग के कारण छात्र अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इससे न केवल छात्रों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचता है।

रैगिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाने के लिए काम करना होगा, जहां छात्र बिना किसी डर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें रैगिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने होंगे और रैगिंग करने वालों को सख्त सजा देनी होगी। रैगिंग के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी और छात्रों को इसके खतरों के बारे में बताना होगा। रैगिंग के खिलाफ एकजुट हों और अपने कॉलेजों को सुरक्षित बनाएं। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना होगा, जहां वे बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा कर सकें।

रैगिंग के प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। रैगिंग के कारण छात्र अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इससे न केवल छात्रों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचता है।

रैगिंग एक गंभीर समस्या है जो न केवल छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, बल्कि यह उनकी जान भी ले सकती है। हमें रैगिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है और अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाने के लिए काम करना होगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जिसमें छात्रों को इसके खतरों और नुकसान के बारे में बताया जा सकता है।

कॉलेजों में छात्र परामर्श केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहां छात्र अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेजों में रैगिंग विरोधी समिति का गठन किया जा सकता है। जो रैगिंग की घटनाओं की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रैगिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने और दोषियों को सख्त सजा देने से रैगिंग की घटनाओं में कमी आ सकती है। शिक्षकों और कर्मचारियों को रैगिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाने और छात्रों की समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।छात्रों के लिए समर्थन प्रणाली स्थापित की जा सकती है, जिसमें वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रयासों से रैगिंग की समस्या का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है और कॉलेजों में एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाया जा सकता है।

बैतूल जिला पुलिस की बड़ी सफलता, आमला में हुई डकैती की घटना का किया खुलासा

डेढ़ लाख नगद और साढ़े तीन लाख के आभूषण बरामद, चार गिरफ्तार

संजय द्विवेदी, बैतूल। 21-22 मई की मध्यरात्रि आमला थाना अंतर्गत रतेड़ा रोड पर रहने वाले गुड़ एवं गल्ला व्यवसायी के घर हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे डेढ़ लाख नकद और लगभग साढ़े तीन लाख रुपये के आभूषण बरामद किए गए हैं। रविवार दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने बताया कि 21-22 मई की रात्रि आमला क्षेत्र के रतेड़ा रोड पर रहने वाले गुड एवं गल्ला व्यवसायी कल्लूलाल प्रजापति के घर में छत के रास्ते घुसकर अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाशों ने मारपीट करते हुए 5 लाख नकद एवं सोने-चांदी के बहुमूल्य आभूषण लूट लिए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना आमला में धारा 310(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। इस गंभीर एवं अंधी वारदात को बडी चुनौती के रूप में लेते पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री झारिया द्वारा एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के निर्देशन में किया गया। टीम में थाना प्रभारी आमला सत्यप्रकाश सक्सेना, चौकी बोडखी से उप निरीक्षक अमित पवार, थाना बीजादेही से उप निरीक्षक रवि शाक्य, थाना भैंसदेही से उप निरीक्षक नितिन उइके सहित कोतवाली,

गंज, मुलताई, साइबर सेल व फिंगरप्रिंट यूनिट के दक्ष अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल किया गया।

तकनीकी विश्लेषण, ओपनसोर्स इंटेलिजेंस के निरंतर प्रयासों से मिली सफलता- जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य, स्थानीय खुफिया जानकारी और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से जिले भर के शातिर अपराधियों की प्रोफाइलिंग करते हुए, घटना का सूत्रधार श्याम पारदी पिता बाबूलाल पारदी निवासी ओझाढाना बैतूल को चिन्हित किया गया, जिसने अपने रिश्तेदारों और साथियों को ग्राम गुलगांव थाना सांची (रायसेन) एवं ग्राम बन थाना गुलाबगंज (विदिशा) से बुलाकर वारदात को अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने श्याम पारदी ओझाढाना बैतूल, शारूख पारदी ग्राम चौथिया थाना मुलताई, राजू उर्फ अंगवाला पारदी गुलगांव, थाना सांची और टल्लू धुर्वे निवासी ओझाढाना बैतूल को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 1,50,000 नकद और लगभग 3,50,000 मूल्य के आभूषण (जिसमें दो सोने के मंगलसूत्र, एक जोड़ी झुमके, अंगूठी, चांदी की दो जोड़ी पायल, सिक्के आदि शामिल हैं) बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और स्कूटी भी जब्त की गई है।

घर का भेदी निकला टल्लू धुर्वे, पूरी योजना को अंजाम देने में की मदद

आरोपी टल्लू धुर्वे, पूर्व में गोरखनाथ कॉलोनी आमला में रहकर कबाड़ व्यवसाय करता था और फरियादी के बड़े पुत्र प्रवीण उर्फ पिंटू के साथ व्यापार में जुड़ा था। वह आमला में ऑटो चलाकर प्रवीण का गल्ला एवं गुड़ उसके घर पहुंचाकर अंदर रखता था। उसी ने श्याम पारदी व अन्य बदमाशों को घटनास्थल की रैकी करवाकर जानकारी दी, जिससे वह इस डकैती का प्रमुख सूत्रधार बन गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं फरार 5 आरोपियों की तलाश कर रही है।

पुलिस टीम का उत्कृष्ट समन्वय और अथक परिश्रम

इस मामले की सफलता में अति. पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के नेतृत्व में गठित टीम अंतर्गत एसडीओपी मुलताई श्री सिंह, थाना आमला प्रभारी सत्यप्रकाश सक्सेना, उनि. अमित पवार, उनि. रवि शाक्य, उनि. नितिन उइके, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी, सहा. उनि. रामेश्वर सिंह, गंभीर सिंह तथा साइबर सेल के आरक्षक राजेंद्र धाडसे व दीपेन्द्र, आरक्षक अनिरुद्ध यादव सहित बड़ी संख्या में सम्मिलित कर्मचारियों के उत्कृष्ट समन्वय तथा अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप यह सराहनीय सफलता मिली।

शारूख की नागपुर पुलिस भी कर रही तलाश

डकैती के मामले से जुड़े शारूख पारदी के विरूद्ध जिले में 8 अपराध दर्ज है, इसके अलावा नागपुर पुलिस को भी इसकी सरगर्मी से तलाश है। एसपी श्री झारिया ने बताया कि यह एक अंतराज्यीय गैंग के अपराधी है, जिन्हें रिमांड पर लेने के बाद और भी अन्य अपराधों की जानकारी मिल सकती है। इस मामले में जब पुलिस ने टल्लू धुर्वे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य पांच आरोपियों की तलाश कर रही है, जो रायसेन व विदिशा जिले के निवासी हैं। इन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार करके शेष लुटे हुए माल की बरामदगी भी जल्द ही की जाएगी।

सालबर्डी में जुआ खेलते 5 आरोपी धराये, मुख्य आरोपी फरार

पुलिस ने जुआ खेलने वाले 5 लोगों को पकड़ा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सालबर्डी में सुखदेव मनिकर अपने घर में जुआ संचालित कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मुलताई, चौकी प्रभारी मासौद, एवं चौकी प्रभारी प्रभात पट्टन की संयुक्त टीम द्वारा सुखदेव मनिकर के सालबर्डी स्थित मकान पर दबिश दी गई। जहां से घर के सामने वाले कमरे से शहजाद खा, हरीफत्तू मल परवाने, राजू पाटिल, शेख वकील निवासी आमबड़ा, सुधीर पूसे निवासी मोर्शी को रंगे हाथों जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी सुखदेव मनिकर कुछ अन्य व्यक्तियों को लेकर घर के अंदर के कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया, पुलिस की कई बार दरवाजा खोलने की चेतावनी के बावजूद उसने सहयोग नहीं किया। उसकी पत्नी एवं अन्य लोगों द्वारा भी दरवाजा खोलने को कहा गया, किंतु आरोपी ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पीछे से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाही के दौरान 42,500 रूपये नगद, 3 मोबाइल फोन, 1 जुआ हिसाब-किताब की कॉपी, कैलकुलेटर, ताश के पत्ते और 88 बियर की बोतलें जब्त कर धारा 13 जुआ अधिनियम एवं धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। वहीं फरार सुखदेव मनिकर की तलाश कर रही है। इस कार्रवाही में थाना प्रभारी मुलताई देवकरण डेहरिया, चौकी प्रभारी प्रभात पट्टन उपनिरीक्षक दिनेश कुमरे, चौकी प्रभारी मासौद उपनिरीक्षक बसंत श्रीवास्तव, प्रआर महिला सोनू ठाकुर, आरक्षक नरेन्द्र कुशवाह, सेवाराम, अरविंद पटेल, आरक्षक महिला मेघा की सराहनीय भूमिका रही।

किसानों को खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ाने, बीज उपचार, मिट्टी परीक्षण, जीरो बजट प्राकृतिक खेती अपनाने की दी सलाह

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग के उप संचालक शैलेंद्र कुमार बडोनिया ने बताया की विकसित कृषि संकल्प अभियान में 8 जून को प्रथम दल द्वारा विकासखंड बैतूल के ग्राम बारहवी, सेलगांव, रेडवा पंचायत, द्वितीय दल द्वारा विकासखंड प्रभात पट्टन के ग्राम पचधार, साईखेड़ा खुर्द, बीसनूर पंचायत, तृतीय दल द्वारा विकासखंड शाहपुर के ग्राम भयावाड़ी, सीलपटी, धपाडामाल पंचायत में, चतुर्थ दल द्वारा विकासखंड आठनेर के ग्राम पंचायत अक्कलवाडी, देहगुड़, उमरी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को बीज उपचार, मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी गई। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारीगण, संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण एवं 2691 किसान उपस्थित रहें।

कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों ने उपस्थित कृषकों को बताया कि खरीफ फसलों की तैयारी से पूर्व उन्नत बीज, खाद प्रबंधन सिंचाई प्रबंधन की जानकारी द्वारा कृषकों को दी गई। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को बताया कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती की विधि है जो पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों पर आधारित है और इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में, सभी कृषि इनपुट, जैसे उर्वरक और कीटनाशक, खेत पर ही बनाए जाते हैं, इसलिए किसानों को बाजार से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती की विशेषता है कि इस विधि में कोई भी रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं किया जाता है यह विधि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और पर्यावरण को संरक्षित करने पर जोर देती है। इस विधि में, किसानों को बाजार से कोई भी इनपुट नहीं खरीदना होता है, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है। इस विधि में, सभी इनपुट प्राकृतिक स्रोतों, जैसे कि गाय के गोबर और गोमूत्र, से प्राप्त किए जाते हैं। जीवामृत एक किण्वित सूक्ष्मजीव संस्कृति है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों को पोषण प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। बीजामृत भी एक किण्वित सूक्ष्मजीव संस्कृति है जो बीजों को उपचारित करने और उन्हें स्वस्थ तरीके से विकसित करने में मदद करती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के विशेष लाभ है कि इस विधि में, जीवामृत और बीजामृत का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। इस विधि से उत्पादित भोजन रसायन-मुक्त होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। इस विधि में, रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। इस विधि में किसानों को बाजार से कोई भी इनपुट नहीं खरीदना होता है, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है। इस विधि से उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है।

आज इन ग्रामों में आयोजित होगा कार्यक्रम

विकसित कृषि संकल्प अभियान के अन्तर्गत आज 9 जून को प्रथम दल विकासखंड चिचोली की ग्राम पंचायत पाठाखेड, बीड रैयत, पडालदा में द्वितीय दल विकासखंड मुलताई के ग्राम पंचायत में बोथिया, ऐनस, उभारिया में तृतीय दल विकासखंड शाहपुर की ग्राम पंचायत कुंडी, सालीमेट, बानाबेहडा में चतुर्थ दल विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत चांदु, रमभा, कुनखेडी में तथा पंचम दल विकासखंड भैसदेही की ग्राम पंचायतें कोथलकुंड, सावलमेंढा, गदराझिरी पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

डोवर से फ्रांस तक 36 किलोमीटर समुद्र में तैराकी करेंगे रामबरन

लहरों से टकराएंगे देश के लिए लहराएंगे तिरंगा, विक्रम अवार्डी रामबरन पाल को शासन से मदद की आस

बैतूल। स्विमिंग कोच एवं विक्रम अवार्डी रामबरन पाल को स्विमिंग एंड पायलटिंग फेडरेशन लंदन की ओर से इंग्लिश चैनल तैराकी के लिए आमंत्रण मिला है। वे सितंबर 2025 में डोवर से फ्रांस तक 36 किलोमीटर समुद्र में तैराकी करेंगे। इसके लिए उन्हें कुल 16 लाख 13 हजार रुपए की आवश्यकता है। यह राशि वे स्वयं नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए शासन और प्रशासन से आर्थिक सहयोग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। रामबरन पाल वर्तमान में नगर पालिका के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कोच के रूप में कार्यरत हैं। उनके मार्गदर्शन में अब तक हजारों युवा तैराकी के क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके हैं। वे खुद उत्कृष्ट तैराक हैं और अपने अनुभव और समर्पण से नई पीढ़ी को भी तैराकी की बारीकियां सिखा रहे हैं। कई युवा उनके प्रशिक्षण से प्रेरित होकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं, जिससे रामबरन का नाम तैराकी के क्षेत्र में भी आदर और सम्मान से लिया जाता है। रामबरन पाल अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 22 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीत चुके हैं। उन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इंग्लिश चैनल पार करना दुनिया की सबसे कठिन तैराकी चुनौतियों में गिना जाता है। इसे स्विमिंग की एवेरेस्ट चढ़ाई माना जाता है। रामबरन के अनुसार यह तैराकी लगातार 14 घंटे चलेगी और इसके लिए वे प्रतिदिन 7 घंटे अभ्यास कर रहे हैं।

रक्तदाता दिवस पर रक्तदाता निकालेंगे बाइक रैली

14 जून को किया जाएगा कार्यक्रम आयोजित

बैतूल। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाएगा। इसको लेकर जिला अस्पताल बैतूल में रक्तदाता दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ.जगदीश घोरे, आरएमओ डॉ रानू वर्मा, जिला रक्त कोष अधिकारी डॉ अंकिता सीते, डॉ अरुण जयसिंहपुरे, डॉ. विनय चौहान की मौजूदगी में रक्तदाताओं और समितियां के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जिला रक्त कोष अधिकारी डॉ अंकिता सीते ने बताया कि बैठक में रेड क्रास सोसायटी,गायत्री परिवार, मॉर्निंग फैमली ग्रुप,प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन,मां शारदा समिति, परशुराम सेवा बैतूल शारदा सहायता समिति, प्रिया आर्ट अकैडमी, पूर्व सैनिक संघ, तपश्री स्कूल, आवाज दो ग्रुप सहित अन्य समितियों के सदस्य मौजूद थे । बैठक में डॉ अरुण जयसिंहपुरे,डॉ विनय चौहान ,संजय (पप्पी)शुक्ला,अमोल पानकर ,मुकेश गुप्ता ,शैलेंद्र बिहारिया, विकास मिश्रा, नितिन अग्रवाल ,पंजाब राव गायकवाड, पिंकी भाटिया, सत्येंद्र नागले ,मनोज तिवारी, सुदामा सूर्यवंशी, दीप मालवी, डॉ सागर निमझे, ओम द्विवेदी, पवन शर्मा, प्रमोद शाह ,कुणाल अहाके, जफर खान, समीर खान ,अकबर खान, राजा कुरैशी सहित समितियां के सदस्य और रक्तदाता उपस्थित थे। डॉ अंकिता सीते ने बताया कि इस वर्ष का नारा गीव ब्लड, गीव होप-टुगेदर वी सेव लीव्स है। रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए रक्तदाता दिवस पर जिला अस्पताल से बाइक रैली निकाली जाएगी। इस रैली में शामिल होने के लिए रक्तदाता गूगल फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करना और जीवन बचाने की इस मुहिम को व्यापक बनाना है। अभियान के उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करना, जिन्होंने रक्तदान कर लोगों की जान बचाई और दूसरों को भी नियमित रूप से रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया।

जिला अस्पताल में कैंसर जागरूकता एवं सुपर स्पेशलिटी शिविर का आयोजन

बैतूल। जिला चिकित्सालय बैतूल के एमसीएच सेंटर में 8 जून को कैंसर जागरूकता एवं सुपर स्पेशलिटी शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश परिहार ने बताया कि शिविर का शुभारंभ बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल एवं सुधाकर पवार द्वारा किया गया।

बैतूल विधायक हेमन्त खंडेलवाल ने कहा कि आज जिंदल अस्पताल भोपाल द्वारा कैंसर सुपर स्पेशलिटी शिविर जिला चिकित्सालय बैतूल में रखा गया है, जिसमें कैंसर एवं संबंधित कई प्रकार की जांचें होगी, कैंसर के प्रति जागरूकता आने से समय पर जांचें करवा कर कैंसर का पता लगने पर शीघ्र से शीघ्र कैंसर का उपचार प्रारंभ करा सकते हैं। शिविर में 250 व्यक्तियों का पंजीयन किया गया जिसमें 60 कैंसर के संभावित मरीज, 50 आर्थोपेडिक मरीज, 45 गायनिक मरीज, 50 मेडिसिन के मरीज, 30 पथरी के संभावित मरीज एवं 15 अन्य मरीज देखे गये। जिंदल अस्पताल भोपाल के स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के साथ-साथ शिविर में आरएमओ डॉ रानू वर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ रूपेश पद्माकर द्वारा मरीजों की जांच की गई।

राज्यस्तरीय खिलाड़ी छात्रा शिक्षक की दरियादिली से दे सकेगी परीक्षा

बैतूल। ग्रामीण अंचलों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं हैं बशर्ते उन्हें सही मार्गदर्शन व संसाधन मिल सके तो बड़ी से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसा ही मामला मजदूर माता-पिता के जरूरतमंद परिवार की छात्रा ढोडवाड़ा स्कूल में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत रहते हुए शालेय कबड्डी प्रतियोगिता में संभाग से राज्य स्तर तक चयनित होकर खेल जगत में नाम करते हुए जिले का नाम रोशन किया। परन्तु आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण और स्वास्थ्य खराब होने के कारण बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। द्वितीय अवसर की परीक्षा में भी पैसों की कमी के कारण वह परीक्षा का फार्म नहीं भर पा रही थी। जब यह जानकारी स्कूल के वाट्सएप ग्रुप में चली तो संस्था में पदस्थ शिक्षक मदनलाल डढोरे ने अवकाश का दिन होने के बाद भी संबंधित छात्रा व परिजनों से गांव जाकर मुलाकात कर राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी छात्रा को आर्थिक सहयोग कर फार्म भरवाया। अब छात्रा द्वितीय अवसर की परीक्षा में सम्मिलित हो पाएगी। पूर्व में भी श्री डढोरे बच्चों के हित में ऐसे उल्लेखनीय कार्य करते रहें हैं। शिक्षक की यह दरियादिली की खबर ग्रामीणों व अन्य शिक्षकों को पता चली तो सभी ने श्री डढोरे की प्रयास की सराहना करते हुए अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बताया। छात्रा व उनके परिवारजनों ने कहा कि ऐसे शिक्षक ही समाज को दिशा देने में सफल होते हैं व भविष्य में इनका यह प्रयास अन्य शिक्षकों को प्रेरित करता है।

फादर्स डे पर एसआईएफ ने लगाया पिता के नाम एक पौधा

वृद्धाश्रम में मनाया फादर्स डे, बुजुर्गों का किया सम्मान

बैतूल। फादर्स डे के अवसर पर रविवार को सामाजिक संगठन सेव इंडिया फैमिली बैतूल (एसआईएफ बैतूल) द्वारा मातोश्री वृद्धाश्रम में पिता के नाम एक पौधा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धजनों के साथ मिलकर केक काटा गया, उनके सम्मान में पौधा रोपण भी किया गया। आयोजन की शुरुआत वृद्धजनों को फूलमालाएं पहनाकर और सम्मान देकर की गई। इसके बाद वृद्धजनों के साथ मिलकर केक काटा गया और उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन भी कराया गया।

आयोजन का उद्देश्य उन वृद्ध पुरुषों को सम्मान देना था, जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण योगदान परिवार और समाज के लिए दिया, लेकिन आज उपेक्षा का जीवन जीने को विवश हैं। पौधा रोपण के जरिए इन पिताओं को श्रद्धांजलि दी गई, जो जीवनभर परिवार के लिए त्याग और छांव की मिसाल बने रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. संदीप गोहे ने बताया कि एसआईएफ बैतूल इस आयोजन को हर वर्ष करता है, लेकिन इस बार पौधा रोपण को विशेष महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसे एक वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के जीवनभर छांव देता है, वैसे ही एक पिता भी अपने पूरे जीवन में परिवार के लिए अडिग खड़ा रहता है। समाज को अब पुरुषों की भावनाओं को भी समझना होगा। इस आयोजन में चंद्रप्रकाश झारे, राजेश उपराले, रूपेश पवार, संचित सोनी, अभिषेक वाल्मीकि, विजय साहू, दिलीप पुआर और देवी प्रसाद मालवीय ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी सराहना मिली। उपस्थित लोगों ने इसे समाज के लिए एक नई मिसाल और प्रेरणा बताया, जिससे यह संदेश जाता है कि पितृत्व भी पूजनीय है और हर पिता अपने जीवन में वटवृक्ष की तरह होता है, जो बिना किसी अपेक्षा के जीवनभर देता ही रहता है।

कार्यक्रम के लिए चंदा नहीं देने पर 35 परिवारों का हुक्का पानी बंद

चोहटा गांव का मामला, बच्चों से व्यवहार रखने पर 5 हजार का जुर्माना

बैतूल। जिले के भीमपुर विकासखंड के ग्राम चोहटा में आदिवासी समाज के एक सैकड़ा लोगों ने मिलकर समाज विशेष का हुक्का पानी बंद कर दिया है। दरअसल शुक्रवार रात को करीब एक सैकड़ा आदिवासियों ने गांव में फेरी लगाकर मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को यह तुगलकी फरमान सुनाया। फरमान के मुताबिक गांव में समाज विशेष 35 परिवारों के बच्चों तक से बात करने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में उनका घर से बाहर तक निकलना बंद हो गया है। आलम यह है कि इन परिवारों को किराना दुकान से सामग्री नहीं बेची जा रही, चक्की पर उनकी पिसाई नहीं की जा रही। जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। साथ ही अपने ही गांव में यह परिवार हर पल अपमानित हो रहे है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम में एक कार्यक्रम के लिए चंदा किया गया था, एक समाज विशेष के कुछ परिवारों ने कार्यक्रम के लिए चंदा नहीं दिया, जिससे आक्रोशित होकर उस समाज के गांव में निवासरत 35परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। ग्रामवासी देवराव बेले ने बताया कि शुक्रवार को अचानक यह मुनादी सुनकर सभी अचंभित है। पाबंदियों का फरमान जारी कर दिया है जिससे समाज के लोग डरे हुए भी है। वे खुद भी यह नहीं जानते कि किस वजह से हुक्का पानी गांव में बंद किया गया। उन्होंने बताया कि नल जल योजना का पानी घरों में आता है इसलिए शुक्र है उन्हें पानी मिल रहा है अन्यथा वर्तमान हालात ऐसे है कि उनके परिवार पानी तक को मोहताज हो जाते। समाज विशेष के लोगों ने जिला प्रशासन और अनुसूचित जाति विभाग के अधिकारियों से हस्तक्षेप करते हुए सभी परिस्थितियों को सामान्य करने की मांग की है। गौरतलब है कि फरमान का पालन न करने पर 5हजार रुपए जुर्मानें का अर्थदंड लगाने की भी मुनादी की गई है।

इनका कहना है -

मैं बाहर हूं। किसी को मामले की जानकारी के लिए भेजता हूं।

- नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर

इस तरह की जानकारी सामने आई है, टीम भेजकर वास्तविकता जानने का प्रयास किया जा रहा है।

- निश्छल एन झारिया, एसपी बैतूल

झोपड़ी में लगी आग, 2 भैंसों की मौत, 5 झुलसीं

शिवपुरी में बचाते समय 1 युवक का हाथ-पैर जला, मुआवजे की मांग

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी जिले के देवगढ़ गांव में रविवार दोपहर एक खेत की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। इस हादसे में दो भैंसों की जलकर मौत हो गई, जबकि पांच भैंसें गंभीर रूप से झुलस गईं। आग से भैंसों को बचाने में एक युवक भी झुलस गया है।

खेत पर बनी झोपड़ी में बंधी थीं सात भैंस

देवगढ़ निवासी फूल सिंह लोधी का खेत गांव से एक किलोमीटर दूर है। उन्होंने खेत पर झोपड़ी बनाकर अपनी सात भैंसों को रखा था। रविवार दोपहर करीब 3 बजे फूल सिंह का छोटा बेटा जीतू लोधी खेत पर सो रहा था। तभी अचानक झोपड़ी से आग की लपटें उठती दिखीं। जीतू ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की।

दो भैंसें आग की चपेट में आकर जल गईं

इस दौरान जीतू ने जान की परवाह किए बिना झोपड़ी में बंधी पांच भैंसों को बाहर निकाला, लेकिन सभी झुलस गईं। वहीं दो भैंसें आग की चपेट में आकर जल गईं। आग से भैंसों को निकालने के दौरान जीतू के हाथ और पैर भी झुलस गए।

ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग

फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस घटना में फूल सिंह लोधी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।

रायसेन में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

रायसेन (नप्र)। रायसेन के भोपाल रोड स्थित सदलतपुर में रविवार शाम 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान ग्राम मुड़ियाखेड़ा निवासी 20 वर्षीय पवन साहू और 26 वर्षीय राजीव विश्वकर्मा के रूप में हुई है। दोनों युवक किसी काम से भोपाल की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वर्तमान में दोनों के शव मॉर्चरी में रखे गए हैं। सोमवार सुबह दोनों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

कगास नदी पर बनेगा 12 फीट ऊंचा पुल

बंधवा कोठार-देवरिहनगांव के बीच छह महीने में होगा निर्माण, विधायक ने किया भूमिपूजन

मऊगंज (नप्र)। मऊगंज जिले में कगास नदी पर एक नए पुल का निर्माण होगा। रविवार को शाम 4 बजे बंधवा कोठार और देवरिहनगांव को जोड़ने वाले इस पुल का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर नरेन्द्र प्रजापति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।पुल चार स्तंभों पर बनेगा और इसकी ऊंचाई 12 फीट होगी। विधायक प्रजापति ने बताया कि इस पुल से

बारिश के मौसम में ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। पहले अल्प वर्षा में भी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतें होती थीं। निर्माण एजेंसी को 6 महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र पांडेय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का 11वां दिन, केंद्रीय कृषि मंत्री बेंगलुरु में किसानों से मिले

बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी में उल्लेखनीय प्रगति : शिवराज सिंह चौहान

बेंगलूर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के अंतर्गत किसानों से संवाद किया। 15 दिवसीय इस अभियान की शुरुआत 29 मई को ओडिशा से हुई थी, जो 12 जून तक चलेगा। अब-तक 11 दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों जिसमें ओडिशा के साथ-साथ जम्मू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश शामिल हैं, का दौरा कर लाखों किसानों से संवाद किया है। इसी कड़ी में आज उन्होंने बेंगलुरु में किसानों से बातचीत की।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में आकर गर्व महसूस हो रहा है। शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के प्रयास सराहनीय हैं। बेंगुलरु ग्रामीण और आस-पास के क्षेत्रों में बागवानी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। किसानों ने स्वयं भी कई प्रकार के शोध व प्रयोग करके कृषि नवाचार में नए अध्याय जोड़े हैं। आज मैंने 'कमलम' (ड्रैगन फरूट) की खेती देखी। 'कमलम' की खेती के बारे में किसानों ने अनुभव साझा किए। मुझे जानकारी मिली की 'कमलम' की खेती में पहले दो वर्ष तक उतना फायदा नहीं होता, लेकिन तीसरे साल के बाद 6 से 7 लाख रुपये आसानी से बचाए जा सकते हैं। टमाटर के खेतों का भी भ्रमण किया मुझे किसान भाइयों ने ही बताया, कई बार कीमतों में उतार-चढ़ाव के बाद भी 3 से 4 लाख रुपये प्रति एकड़ कमाया जा सकता है।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि 'लैब से लैंड' जुड़ना जरूरी है। रिसर्च की रीयल टाइम में किसानों तक पहुंच हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जलवायु और क्षेत्र की विशेषता के अनुसार फलों, सब्जियों और फसलों की उपज की सही जानकारी

किसानों तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' की परिकल्पना की है। इसलिए विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान जरूरी है। बिना कृषि के विकास संभव नहीं है। आज भी 50 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जीडीपी में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है। साथ ही इस वर्ष चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7.5 प्रतिशत है, जिसमें कृषि का योगदान 5.4 प्रतिशत है। कृषि में 1 या 2 प्रतिशत की विकास दर बड़ी मानी जाती है। उस लिहाज में यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार हम कृषि क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसान भाइयों-बहनों को प्रणाम करता हूं, वह चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन आगे भी अनंत संभावनाएं हैं।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमें चार प्रमुख लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिनमें शामिल हैं-

- 145 करोड़ आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा
- पोषणयुक्त आहार
- किसानों के लिए कृषि क्षेत्र को लाभ में बदलना
- मिट्टी की उर्वरक क्षमता को सुरक्षित रखना

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इन्हीं निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 'लैब को लैंड' से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर वहां कि क्षेत्र विशेष की जानकारियों के आधार पर, मिट्टी की उर्वरकता की आवश्यकतानुसार, जलवायु व अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किसानों को सही किस्मों व पद्धति के जरिए कृषि में उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दे रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह ने नकली बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रति भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गुणवत्ताहीन बीज या कीटनाशक बनाने वालों के प्रति सरकार सख्ती से पेश आएगी। कानून बनाया जा रहा है। ऐसे कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री चौहान ने कहा कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 16 हजार वैज्ञानिक खेतों में किसानों के पास जाकर शोध की जानकारी दे रहे हैं। 'एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम' विजन के साथ हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सम्मिलित प्रयासों से भारत को विश्व का 'फूड बास्केट' बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। हम अपने देश की जरूरतें भी पूरी करेंगे और विदेशों में निर्यात की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की समृद्धि के लिए हरसंभवन प्रयास किए जा रहे हैं। किसान सीधे अपनी उपज बेच सके, बिचौलियों की भूमिका कम हो इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) बनाई गई है। आलू, प्याज और टमाटर इन तीन फसलों के लिए यदि कोई किसान कम कीमत के कारण अपने क्षेत्र की जगह बड़े शहरों या ऐसे राज्यों जहां उनकी उपज की कीमत अधिक है, वहां ले जाकर अपनी फसल को बेचना चाहे तो ऐसी स्थिति में परिवहन में होने वाली परिचालन लागत का खर्चा केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। ऐसा तालमेल करने से किसानों को भी उचित दाम मिल जाएगा और जिस क्षेत्र में दाम अधिक है वहां उत्पादन पहुंचने से दाम भी संतुलित हो जाएंगे। अगर भंडारण को लेकर भी सहायता की आवश्यकता होगी तो केंद्र द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना इसी साल निर्मित की गई है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही अन्य कई प्रयास किए जा रहे हैं।

अंत में श्री चौहान ने कहा कि कृषि मंत्री, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विज्ञान केंद्र व अन्य उपक्रमों से जुड़े प्रत्येक वैज्ञानिक की असली जिम्मेदारी यही है कि किसान भाइयों-बहनों तक शोध की सटीक जानकारी सही समय में पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी किसानों से कहा कि सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर ना रहें। आगे बढ़ते हुए कृषि विविधिकरण, प्रोसेसिंग का मार्ग भी चुनें। निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर संभव तरीके से कृषि को किसानों के लिए फायदे में बदलने की कोशिश कर रही है। हर स्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की समृद्धि ही हमारा लक्ष्य है।

इस अवसर पर सांसद व पूर्व मंत्री एम सी सुधाकर, विधायक, एस आर विश्वनाथ, डॉ. एस के सिंह, महानिदेशक बागवानी संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. राघवेंद्र भट्टा, महानिदेशक, पशु विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, डॉ. वी. सुब्रमण्यम डायरेक्टर बागवानी संस्थान बेंगलुरु, वैज्ञानिक, छात्र, व किसान शामिल रहे।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुपुत्र डॉ. अभिमन्यु एवं डॉ. इशिता के सगाई समारोह में शामिल हुए और शुभकामनाएं दीं।

गांधी मेडिकल कॉलेज में टीएमएस से ब्रेन डिसऑर्डर का इलाज

ओसीडी से लेकर सिजोफ्रेनिया तक में कारगर, 15 मिनट के सेशन से मिलेगा आराम

भोपाल (नप्र)। ऐसे मानसिक रोगी जिन पर दवाओं असर नहीं होता उनको भी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में ट्रांसक्रोनियल मैग्नेटिक स्टीमुलेशन (टीएमएस) मशीन मौजूद है। इस मशीन से गैर-आक्रामक उपचार पद्धति से ओसीडी , सिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक समेत अन्य ब्रेन डिसऑर्डर का इलाज सिर्फ 15 से 20 मिनट के सेशन में किया जा रहा है।

मेगनेटिक फील्ड के उपयोग से होता है इलाज- टीएमएस मशीन मस्तिष्क के खास भागों को एक्टिव करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों (मेग्नेटिक फील्ड) का इस्तेमाल करती है। इसमें एक क्वाइल होती है। जिसे सिर पर रखा जाता है। यह क्वाइल एक छोटा, केंद्रित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। जब यह मेग्नेटिक फील्ड दिमाग में प्रवेश करता है, तो यह न्यूरॉन्स (मस्तिष्क की कोशिकाओं) में छोटे विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। जिससे ये न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। कई मामलों में इसकी मदद से न्यूरॉन्स को निष्क्रिय भी किया जाता है। टीएमएस मशीन मस्तिष्क के संबंधित भाग को सक्रिय करने के लए मेग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉ. जेपी अग्रवाल ने बताया कि मानसिक बीमारियों में अक्सर मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे सेरोटॉनिन, डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन का संतुलन बिगड़ जाता है। मेग्नेटिक सिस्टम में क्वाइल से चुंबकीय किरणें निकलती हैं, जो इस असंतुलित हिस्से को संतुलित कर देती हैं। इस तकनीक की सफलता दर 80 से 90 प्रतिशत है। खासकर उन 50 प्रतिशत मरीजों के लिए जिन पर दवाएं असर नहीं करती हैं।3

बुरहानपुर में बीटी कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग

बुरहानपुर (नप्र)। बुरहानपुर के उद्योग नगर स्थित रोहित पोद्दार की बीटी कॉटन इंडस्ट्रीज में रविवार शाम करीब 6 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि धुएं का गुबार 5 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। आग की सूचना मिलते ही नगर पालिक निगम, शाहपुर और नेपानगर से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं।नगर निगम फायर अधिकारी बसंत पाटिल के मुताबिक, 3 फायर फाइटर और एक टैंकर की मदद से आग बुझाने का काम चल रहा है।

सुरक्षा के चलते फैक्ट्री के पास स्थित रिहायशी इलाकों और पास की फैक्ट्रियों को खाली कराया गया।शाम 7 बजे चार थानों से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को हटाया गया।

प्रशासन मौके पर, कोई जनहानि नहीं- एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने बताया कि आसपास के जिलों से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड बुलाई गई हैं। अब तक किसी जान-माल की हानि की सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को बड़ा नुकसान होने की आशंका है।

आग का कारण अब तक अज्ञात- गणपति नाका थाना, किशोर सिंह मोरे के अनुसार, आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर डटी हुई हैं।

जबलपुर में बी.टेक छात्र ने किया सुसाइड

सुसाइड नोट में लिखा- कुछ नहीं कर पा रहा हूं; परिजन बोले- बेटे का दांत टूटा, जबरदस्ती हुई

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में बी.टेक फर्स्ट ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र का नाम प्रियांशु त्रिपाठी है, जो मैहर जिले का रहने वाला था। जबलपुर में वह शास्त्री नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

शनिवार देर रात जब मकान मालिक ने देखा कि काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला है, तो झांककर देखा तो प्रियांशु फंदे में लटका हुआ था। सूचना पर पहुंची तिलवारा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सुसाइड नोट में लिखा- कुछ नहीं कर पा रहा- प्रियांशु के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने लिखा है कि वह अपने माता-पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि पुलिस नोट की अन्य बातों की भी जांच कर रही है। छात्र के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से वह काफी परेशान रहने लगा था। उसे कुछ विषयों में बैक आई थी और उसने लोगों से मिलना-जुलना भी कम कर दिया था।

परिजन बोले- बेटे के साथ जबरदस्ती हुई, उसका दांत टूटा था

रविवार सुबह छात्र के परिजन मैहर से जबलपुर पहुंचे। उन्होंने छात्र की आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार, प्रियांशु का शव दो गमछों से बने फंदे पर मात्र ढाई फीट ऊंचाई पर लटका था, जबकि उसके पैर जमीन से छू रहे थे। इसके अलावा मृतक का एक दांत टूटा हुआ था, जिससे जबरदस्ती या संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने छात्र के मोबाइल की साइबर जांच और सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच की मांग की है। छात्र के दोस्तों के मुताबिक, 4 जून को आए रिजल्ट के बाद से ही वह तनाव में था और मिलना-जुलना भी कम कर दिया था।

पुलिस कर रही जांच

तिलवारा थाना एएसआई पी.एल. बंसल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, साइबर एनालिसिस और सुसाइड नोट की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उधर, छात्र का अंतिम संस्कार उसके गृह ग्राम करौंदी में किया जाएगा।

समर कैंप में बच्चों ने सीखे जीवन के मूल मंत्र

ब्रह्माकुमारीज़ सेवा केंद्रों पर हुआ आत्मविकास व संस्कार आधारित शिविर

विभिन्न स्कूलों व डांस स्टूडियोज़ में भी बच्चों को दी जा रही है आध्यात्मिक शिक्षा

भोपाल। गर्मियों की छुट्टियों को सिर्फ मौज-मस्ती तक सीमित न रखते हुए, ब्रह्माकुमारीज़ संस्था द्वारा बच्चों के लिए संस्कार व आत्मविकास पर आधारित समर कैंप्स का आयोजन किया गया। एग्जॉटिका सेवा केंद्र, विजय नगर सेवा केंद्र और ग्रीन एकड़ सेवा केंद्र पर आयोजित इन विशेष शिविरों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

शिविर में फन गेम्स, ड्राइंग, नृत्य, संगीत, कहानियाँ, समूह चर्चा, योग व राजयोग मेडिटेशन जैसे बहुआयामी सत्र आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बच्चों में एकाग्रता, आत्म-विश्वास, सकारात्मक

सोच और नैतिकता जैसे मूल्यों का विकास करना रहा।

'मैं कौन हूँ' से लेकर 'सच्ची खुशी क्या है' तक के विषयों पर संवाद

ब्रह्माकुमारीज़ की वरिष्ठ बहनों और प्रशिक्षित शिक्षकों ने बच्चों से आत्म-चिंतन पर आधारित प्रश्नों जैसे मैं कौन हूँ?, मेरे संस्कार कैसे बनते हैं? और शांति कहाँ मिलती है? जैसे विषयों पर संवाद कराए। बच्चों ने इन प्रश्नों को सहजता से समझा और अपनी जीवनशैली में उतारने की प्रेरणा ली।

ध्यान (राजयोग मेडिटेशन) के सरल अभ्यासों के माध्यम से बच्चों को अपने विचारों की शक्ति को पहचानने और मानसिक शुद्धता की ओर अग्रसर होने का प्रशिक्षण दिया गया।

स्कूलों और निजी संस्थानों में भी पहुंच रही ब्रह्माकुमारीज़ की सेवा

सिर्फ सेवा केंद्रों तक सीमित न रहते हुए, ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों, डांस स्टूडियोज़ एवं अन्य निजी समर कैंप्स में भी विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बच्चों को नैतिक शिक्षा, तनाव प्रबंधन, मन की एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर रोचक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इन संस्थानों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह आज की पीढ़ी को तकनीकी दुनिया के तनाव से दूर ले जाकर एक संतुलित व मूल्यनिष्ठ जीवन की ओर प्रेरित करने का श्रेष्ठ माध्यम है।

समापन पर प्रमाणपत्र व प्रस्तुतियाँ

शिविर के अंतिम दिन सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। बच्चों ने नृत्य, अभिनय, गीत और भाषणों के माध्यम से शिविर में सीखी बातों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कई अभिभावक इस दृश्य से भावुक हो उठे और संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे 'संस्कारों की पाठशाला' बताया।

संस्था का संदेश

ब्रह्माकुमारीज़ का यह प्रयास एक संदेश देता है कि यदि प्रारंभ से ही बच्चों को आत्मिक शक्ति, नैतिक मूल्यों और शांति की सही दिशा मिले, तो वे एक संतुलित, सफल और मूल्यवान जीवन जी सकते हैं।

मध्यप्रदेश में 41 डॉक्टरों और अधिकारियों के तबादले

भोपाल के नए सीएमएचओ बने डॉ. मनीष शर्मा, बोले- पहली प्राथमिकता कोरोना को फैलने से रोकना

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) सहित कुल 41 चिकित्सकों, विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये तबादले सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति वर्ष 2025 के तहत किए गए हैं। इन्हें प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा शनिवार देर रात आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार, भोपाल का नया सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा को बनाया गया है। वे अब तक ग्वालियर में प्रभारी उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने कहा कि भोपाल के सीएमएचओ का पदभार ग्रहण करने के साथ ही उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 को फैलने से रोकने की दिशा में काम करना होगी।

वहीं, भोपाल के वर्तमान सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी को वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन 41 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

- डॉ. राजेश कुमार अठ्या -सीएमएचओ, दमोह
- डॉ. राज सिंह ठाकुर -सीएमएचओ, कटनी
- डॉ. भरत कुमार खटीक - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी
- डॉ. राजेश प्रसाद तिवारी - प्रभारी, सीएमएचओ, पन्ना
- डॉ. मनोज कुमार हुरमाडे - प्रभारी, सीएमएचओ, बैतूल
- डॉ. दिनेश खत्री, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, राजगढ़
- डॉ. हरिनारायण मांड्रे - प्रभारी, सीएमएचओ, रायसेन
- डॉ. बी. के. वर्मा - प्रभारी, सीएमएचओ, दतिया
- डॉ. दर्पण टोके - प्रभारी, सिविल सर्जन, बुरहानपुर
- डॉ. प्रदीप मोजेश - मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, बुरहानपुर
- डॉ. वी. एस. चंदेल - प्रभारी, सीएमएचओ, उमरिया
- डॉ. शोभाराम रोशन - संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, सागर
- डॉ. धरित्री जे. मोहंती -सीएमएचओ, मंडला
- डॉ. पवन जैन - प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
- डॉ. एम. के. जोशी - संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, उज्जैन
- डॉ. जितेन्द्र राजपूत - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन
- डॉ. राजेश सिसोदिया - जिला चिकित्सालय, हरदा
- डॉ. किरण वाडिवा - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. भूरे सिंह सैत्या - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, ग्वालियर
- डॉ. पवन शर्मा - शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, ग्वालियर
- डॉ. नीरज कुमार - शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, भिंड
- डॉ. अलका त्रिवेदी - प्रभारी, सीएमएचओ, अशोकनगर
- डॉ. के. सी. सरोत - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. माधव हसानी - प्रभारी, सीएमएचओ, इंदौर
- डॉ. राष्टेन्द्र कुमार खाड्योत - प्रभारी, सीएमएचओ, नीमच
- डॉ. रामहित कुमार - जिला स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा
- डॉ. मनीष शर्मा -सीएमएचओ, भोपाल
- डॉ. प्रभाकर तिवारी - वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल
- डॉ. दिनेश देहलवार - प्रभारी, सीएमएचओ, मालवा
- डॉ. राजेश गुप्ता - जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी, बड़वानी
- डॉ. मनोज कौरव - डीएचओ, ग्वालियर
- डॉ. नरसिंह गेहलोत - सीएमएचओ, नर्मदापुरम
- डॉ. सनेराम परस्ते - प्रभारी, सिविल सर्जन, अनूपपुर
- डॉ. अनिल झामनानी - प्रभारी, सीएमएचओ, निवाड़ी
- डॉ. रामकुमार गुप्ता - सीएमएचओ, ग्वालियर
- डॉ. प्रदीप कुमार जैन - शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, ग्वालियर
- डॉ. यशपाल सिंह - प्रभारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, रायसेन
- डॉ. मुकेश जैन - शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, दमोह
- डॉ. एस. के. त्रिपाठी - प्रभारी, सीएमएचओ, पन्ना
- डॉ. राजेश परिहार - जिला परिवार कल्याण अधिकारी, बैतूल
- डॉ. सुशीला यादव - चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सागर

सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु की सगाई

खरगोन के बड़े किसान की बेटी डॉक्टर इशिता बनेंगी यादव परिवार की बहू

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की सगाई भोपाल में एक सादे समारोह में हुई। खरगोन के सेल्दा गांव की रहने वाली इशिता सीएम मोहन यादव के परिवार की बहू बनेंगी।

डॉ. इशिता सेल्दा के बड़े किसान दिनेश यादव (पटेल) की बेटी हैं। सगाई समारोह दोनों परिवारों के परिजन और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में सीएम हाउस में हुआ। इस दौरान बीजेपी के भी कई नेता मौजूद रहे।

सीएम डॉ. मोहन यादव और सीमा यादव के दो बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे और बेटी की शादी पहले ही हो चुकी है। सीएम ने बेटे की सगाई की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- बाबा श्री महाकाल और श्री गोपाल कृष्ण की परम कृपा और पूज्य पिता और माताश्री के आशीर्वाद

से पुत्र चिरंजीवी डॉ. अभिमन्यु यादव की सगाई, खरगोन के दिनेश यादव जी की सुपुत्री डॉ. इशिता यादव के साथ संपन्न हुई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत कई गणमान्य नेता शामिल थे।

पारंपरिक रीति से रिंग सेरेमनी, दोनों हैं डॉक्टर

सीएम हाउस में आयोजित सगाई समारोह में दोनों ने पारंपरिक पूजन के बाद एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। डॉ. अभिमन्यु यादव एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज भोपाल से मास्टर्स इन सर्जरी कर रहे हैं, वे सेकेंड ईयर में हैं। वहीं डॉ. इशिता एमबीबीएस कर रही हैं।

एमपी में 10 जून के बाद मानसून की एंट्री

8 जिलों में बारिश का अलर्ट; 9-10 जून को ग्वालियर-चंबल में लू चलेगी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होगी। इससे पहले प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज-चमक के साथ लू भी चलेगी। दक्षिणी हिस्से के 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है, जबकि 9 और 10 जून को ग्वालियर-चंबल में हीट वेव यानी, लू भी चल सकती है। इससे पहले शनिवार को इंदौर, नर्मदापुरम-बड़वानी में बारिश हुई। वहीं, 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 10 दिन से मानसून महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। इस वजह से एमपी में इसकी एंट्री लेट हो रही है। अगले 3 से 4 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना कम ही है।

इन जिलों में आज मौसम बदला रहेगा

बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी में आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट है। वहीं, सोमवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना में लू का अलर्ट है। सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में गरज-चमक और बारिश वाला मौसम रह सकता है। इंदौर, नर्मदापुरम, बड़वानी जिले में बारिश, 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार प्रदेश में शनिवार को मौसम के दो रंग देखने को मिले। इंदौर, नर्मदापुरम और बड़वानी के सेंधवा में हल्की बारिश हुई। वहीं, ग्वालियर समेत 13 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, खजुराहो और गुना में पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, ग्वालियर, नौगांव, शाजापुर, सतना, टीकमगढ़ और शिवपुरी में 41 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। उज्जैन, सीधी, रीवा, सागर और रतलाम में तापमाान 40.2 से 40.8 डिग्री तक रहा।

दुकानों पर महंगी शराब बिकने पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया

उमंग सिंघार का सरकार पर हमला, पूछा कि जिम्मेदार कौन!

भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब की निर्धारित कीमतों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए सरकार और आबकारी विभाग की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब दुकानों पर शराब तय से ज्यादा दाम पर बेची जा रही है और इसमें अधिकारियों से लेकर शराब माफियाओं तक की मिलीभगत है।

सिंघार ने लिखा कि जब बाकी सभी चीजें एमआरपी पर मिलती है, तो शराब ही मनमाने दामों पर क्यों बिक रही है! उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक संगठित खेल है, जिसमें अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत है और यह राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं। उन्होंने बताया कि आबकारी आयुक्त ने 1 अप्रैल से सभी शराब दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा करने का आदेश दिया था। लेकिन, इंदौर जैसी बड़ी जगहों पर 2 महीने हो चुके है अब तक यह आदेश लागू नहीं हुआ है। जबकि, जबलपुर में कलेक्टर ने कार्रवाई की है।

सिंघार ने उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा से भी सवाल किया कि क्या यह जानकारी उनके पास नहीं पहुंची या फिर वे जानबूझकर चुप हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच और जवाबदेही की मांग की है। साथ ही दोहराया कि वे शराबबंदी के समर्थक हैं, लेकिन जब तक शराब बिक रही है, तब तक वह कम से कम तय कीमत पर तो बिके।

उमंग सिंघार की इस सोशल मीडिया पोस्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि, आबकारी विभाग के आयुक्त ने ही प्रदेश की सभी शराब दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने और निर्धारित कीमत पर शराब बेचने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन, इस आदेश को शराब माफिया ने नहीं माना। क्योंकि, आबकारी विभाग ने कोई सख्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि आबकारी विभाग में आयुक्त के आदेश को ही अफसरों ने नजरअंदाज क्यों किया और इसके पीछे कौन है!

चलती ट्रेन से फिसला युवक, आरपीएफ जवान ने बचाया

भोपाल स्टेशन पर टला बड़ा हादसा ; प्लेटफार्म-कोच के बीच में फंस रहा था युवक

भोपाल (नप्र)। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन पर चढ़ते समय एक युवक का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। वह प्लेटफार्म और कोच के बीच में फंसने लगा। तभी आरपीएफ जवान ने दौड़ लगाई और खींचकर युवक को बचा लिया।

मामला शनिवार शाम का है, जो रविवार को सामने आया है। जानकारी के अनुसार, शाम को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म-1 से रवाना हो रही थी। इसी दौरान भोपाल के गांधीनगर निवासी अमरपाल सिंह प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अपने परिजनों को ट्रेन में बैठाने आए थे। अधिक सामान चढ़ाने के लिए कोच में गए थे। ट्रेन के चलने के बाद जब उन्होंने नीचे उतरने का प्रयास किया, तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वे फिसलकर कोच और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़े।

आरक्षक ने तुरंत खींचा- मौके पर मौजूद आरपीएफ आरक्षक कृष्ण कुमार ने हादसा होते देख दौड़ लगाई और युवक को खींचकर बाहर निकाला। जिससे उसकी जान बच गई। युवक को केवल मामूली खरोंचें आईं। जिनका उपचार स्टेशन पर स्थित डिस्पेंसरी में किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि आरक्षक की सतर्कता और त्वरित निर्णय ने एक संभावित गंभीर हादसे को टाल दिया। उन्होंने यात्रियों से यह भी अपील की कि वे चलती ट्रेन से चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें और केवल गाड़ी के पूर्णतः रुकने पर ही चढ़ें या उतरें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार की सुबह मुख्यमंत्री निवास पर गायों को दुलार किया और उन्हें रोटी खिलाई।

3 साल का बच्चा सीकर में किडनैप

मां और दादी के साथ खाटू श्याम दर्शन के लिए गया था, स्टेशन पर किडनैपर ने की दोस्ती

भोपाल (नप्र)। भोपाल से राजस्थान सीकर गए एक 3 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। बच्चा अपनी दादी और मां के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया। जैसे ही जयपुर स्टेशन पर पहुंचे, एक युवक उनसे मिला और कहा कि वह भी खाटू श्याम जा रहा है। इसके बाद वह उनके साथ चल दिया।

खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचने पर युवक ने भीड़ का बहाना बनाया और बच्चे को अपने पास रखकर मां-दादी को दर्शन के लिए भेज दिया। जब दोनों महिलाएं दर्शन करके लौटीं तो न तो बच्चा मिला और न ही वह युवक। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों में भी तलाश अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है।

एकादशी पर दर्शन करने पहुंचे थे

भोपाल से एकादशी पर दर्शन के लिए आए परिवार के साथ बड़ी वारदात हो गई। मां ने बताया कि 6 जून को वह 3 साल के बेटे रक्षम और सास आशा के साथ ट्रेन से जयपुर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर एक युवक से मुलाकात हुई, जो खाटू जाने की बात कहकर उनके साथ हो लिया।

खाटू पहुंचने पर युवक ने मासिक मेले की भीड़ का बहाना बनाया। मां-दादी को दर्शन के लिए भेज दिया और बच्चे को अपने पास रख लिया। जब दोनों महिलाएं लौटीं तो बच्चा और युवक गायब थे।

थाने के आसपास भी घूमा, फिर गायब हो गया

पुलिस जांच में सामने आया कि किडनैपर बच्चे को एक दुकान पर ले गया, जहां उसे फरूटी पिलाई। वह पुलिस थाने के आसपास भी घूमा, फिर कहीं गायब हो गया। 7 जून की शाम को मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देश पर कई टीमें सर्चिंग कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आसपास के इलाकों में तलाश जारी है।

पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर परीक्षा देने वाले 22 अभ्यर्थियों के विरुद्ध 21 प्रकरण पंजीबद्ध

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले अभ्यर्थियों पर की जा रही सख्त कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्त कार्रवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज पुलिस मुख्यालय के पुराने कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था श्री अंशुमान सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी तथा रेडियो में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में ऑनलाइन लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 6,52,057 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। प्रक्रिया के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार 55,220 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा चयन शाखा, मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर से 20 नवम्बर के मध्य आयोजित की थी। संपूर्ण प्रक्रिया के उपरांत कुल 6423 अभ्यर्थी (5090 पुरूष एवं 1333 महिला) का चयन किया गया था।

द्वितीय चरण के शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान नवम्बर 2024 में परीक्षा केन्द्र मुरैना में 05 अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु भेजा गया, जिन्हें संदिग्ध पाते हुए, परीक्षा में शामिल न कर उक्त उम्मीदवारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही

की गई थी।

इस अनुभव के आधार पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अंतिम परिणाम जारी होने के उपरांत सभी सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उनकी आवंटित इकाईयों से बायोमेट्रिक एवं आधार हिस्ट्री की जांच पुनः कराये जाने हेतु दिनांक 21-04-2025 को निर्देश जारी किये गये। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में कुछ जिले में संदिग्ध रूप से भिन्नता पाये जाने पर बारीकी से जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के पूर्व अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक संशोधन कराया गया था तथा लिखित परीक्षा के ठीक बाद उनके द्वारा पुनः आधार कार्ड का बायोमेट्रिक संशोधन कराया गया। ऐसे अभ्यर्थियों पर संदेह के आधार पर इनकी जांच कराई गई, जिसमें इनके हस्ताक्षर नूमना, हस्तलिपि, फिंगर प्रिंट लिये गये। साथ ही परीक्षा के दौरान इनके द्वारा दिये गये फिंगर प्रिंट, हस्तलिपि, के नमूने को प्राप्त कर उनकी जांच कराई गई। अभ्यर्थियों की वास्तविक लोकेशन के संबंध में तकनीकी रूप से भी जांच कराई गई, जिसमें भिन्नता पाये जाने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। अभी तक कुल 21 प्रकरण 22 अभ्यर्थियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये जा चुके है, जिसमें मुरैना में 07, शिवपुरी-06, श्योपुर-02 तथा इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ तथा शहडोल में 01-01 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आये हैं कि कुछ आधार कार्ड बेण्डरों द्वारा अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों के आधार कार्ड को बिना पूरी तरह जांच किये संसोधन के लिए अपने सिस्टम में अपलोड किया गया था।

परीक्षा पास करने वाले हर आरक्षक की अंकसूचियों की होगी जांच

पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 में फर्जीवाड़ा कर पास हुए नवआरक्षकों के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ग्वालियर-चंबल में अब तक 22 आरक्षक पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने अपनी जगह किसी सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पास की है। जांच में जुटे अफसरों को अब संदेह है कि कई आरक्षकों की बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट भी फर्जी हो सकती है, इसलिए नवआरक्षकों की अंकसूचियों की भी जांच करवाई जाएगी।

धोखाधड़ी व परीक्षा अधिनियम की धाराओं में एफआईआर

गौरतलब है, कि आरक्षक भर्ती के बाद हर जिले को नवआरक्षकों का कोटा दिया गया है। मुरैना जिला पुलिस को 38 और 5वीं बटालियन को 106 आरक्षकों का कोटा मिला है। इनमें से बटालियन में अब तक पांच ऐसे आरक्षक पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने आधार कार्ड में फोटो व बायोमैट्रिक फिंगर प्रिंट बदलवाकर साल्वर के जरिए भर्ती परीक्षा पास की। जिला पुलिस भी ऐसे दो नवआरक्षक पकड़ चुकी है। इन सातों पर धोखाधड़ी व परीक्षा अधिनियम की धाराओं में एफआईआर हो चुकी है।